रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1986/भाद्रपद 15, 1908

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1986/BHADRA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1986

सूचना

का. आ. 3021.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी. शेषागिरि राव, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे चिराला व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(56)/86-न्या.]

आर. एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 18th August, 1986

NOTICE

S.O. 3021.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri B. Seshagiri Rao, Advocate for appointment as a Notary to practise in Chirala.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(56)|86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

का. आ. 3022.—गृह मंत्रालय की तारीख 7-2-86 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग (नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

1. कार्यालय, कमांडेंट, 75 बटालियन,
   केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, झालपारा,
   गोहाटी-22, असम ।
2. कार्यालय, कमांडेंट सिगनल्स ग्रुप केन्द्र,
   केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच (मध्य प्रदेश) ।
3. कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक,
   केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, बल, मद्रास ।
4. कार्यालय, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक,
   ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आवडी (मद्रास) ।

5. कार्यालय, कमांडेंट, 5वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नागपुर-19।

6. कार्यालय, प्रिंसिपल, रंगरूट प्रशिक्षण, केन्द्र-2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आवडी, मद्रास-65।

7. कार्यालय, कमांडेंट, 64वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मार्फत 99 ए पी. ओ.।

8. कार्यालय कमांडेंट, प्रथम सिगनल बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, बल नई दिल्ली।

9. कार्यालय, कमांडेंट, 3 सिगनल बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुर (उत्तर प्रदेश)।

10. जनगणना कार्य निदेशालय, असम गोहाटी।

11. जनगणना कार्य निदेशालय, सिक्किम, गंगटोक।

12. कार्यालय, कमांडेंट, 10वीं बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मिर्थि जिला, पिथौरागढ़, (उत्तर प्रदेश)।

13. कार्यालय, एच.एफ.सी. लिमिटेड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दुर्गापुर-12-पश्चिमी बंगाल।

14. अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

15. कार्यालय, निदेशक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जयपुर।

[सं. 12017/1/86-हिंदी]
मदन मोहन शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th August, 1986

S.O. 3022.—In supersession of notification of even No. dated 7-2-86, the Central Government hereby notifies the following office of the Ministry of Home Affairs, the 80 percent staff thereof having acquired the working knowledge of Hindi under sub-rule (4) 10 of the Official Languages (use for Official purposes of the Union), Rules, 1976.

1. Office of the Commandant, 75 Battalion, CRPF, Khanapara, Gauhati-22, Assam.
2. Office of the Commandant Signal Group Centre, CRPF, Nimach (M.P.).
3. Office of the Dy. Inspector General of Police, CRPF, Madras.
4. Office of the Additional Dy. Inspector General of Police, Group Centre, CRPF, Awadi, Madras.
5. Office of the Commandant, 5 Battalion, CRPF., Nagpur —19.
6. Office of the Principal, Rangroor, Training Centre-2, CRPF., Awadi, Madras-65.
7. Office of the Commandant, 64 Battalion, CRPF, C/o 99 APO.
8. Office of the Commandant, 1st Signal Battalion, CRPF., New Delhi.
9. Office of the Commandant, 3 Signal Battalion, CRPF., Rampur (UP).
10. Directorate of Census Operation. Assam, Gauhati.
11. Directorate of Census Operation. Sikkim, Gangtok.
12. Office of the Commandant, 10 Battalion, ITBP, Mirthi, Distt. Pithoragorh, (UP).
13. Office of the Commandant, HFC. Ltd., CISF. Durgapur, West Bengal
14. Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi.
15. Office of the Director for Scheduled Caste & Scheduled Tribes, Jaipur.

[No. 12017/1/86-Hindi]
M. M. SHARMA, Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1986

का.आ. 3023.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) दूसरा संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 की पांचवी अनुसूची के पैरा 2 में अंत में किन्तु प्रथम परन्तुक से पहले, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के समूह "ख" समूह "ग" और समूह "घ" कर्मचारिवृन्द को भारत नियम 12 के उप-नियम (2) के अधीन अग्रिम नीचे उल्लिखित अधिकारियों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा :—

(i) अपर महानिदेशक मौसम विज्ञान (अनु.), पुणे
(ii) उप महानिदेशक मौसम विज्ञान (डब्लू. एफ.), पुणे
(iii) उप महानिदेशक मौसम विज्ञान (आई. एस.) पुणे
(iv) निदेशक (एग्रीमेट) पुणे
(v) प्रादेशिक निदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली।
(vi) उप महानिदेशक मौसम विज्ञान (आई.पी.), नई दिल्ली।
(vii) भारसाधक मौसम विज्ञानी सी.एस.ओ., भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, शिलांग।
(viii) निदेशक इंडियन पोजिशनल एस्ट्रोनोमी सेन्टर मौसम विज्ञान विभाग कलकत्ता।

[संख्या 13(2)-पेंशन/85-जी.पी.एफ]
हजारा सिंह, उप सचिव

टिप्पण :—साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 का.आ. सं.-3000 तारीख 1-12-1960 के रूप में प्रकाशित किए गए थे। नियमों का पुनःमुद्रण 30-11-1978 (तक संशोधित) 1979 में मुद्रित किया गया था। पश्चात्वर्ती संशोधन, नीचे उल्लिखित अधिसूचना द्वारा किए गए :—

1. एफ 13(9)/77-ई वी (बी) तारीख 13-12-1978
2. एफ 13(5)/78-ई वी (बी) तारीख 23-4-1979
3. एफ 13(11)/78-ई वी (बी) तारीख 30-5-1979
4. एफ 13(7)/78-ई वी (बी) तारीख 18-6-1979
5. एफ 17(5)-ई वी (बी)/78 तारीख 18-6-1979
6. एफ 19(15)-पैन/76(जीपीएफ) तारीख 9-9-1979
7. एफ 9(2)-ई वी (बी)/पैन/78-जीपीएफ तारीख 13-11-1979
8. एफ 10(10)-पैन/79-जीपीएफ तारीख 3-3-1980
9. एफ 20(22)-ई वी (बी)/पैन/79-जीपीएफ तारीख 18-4-80
10. एफ 13(6)-पैन/79-जीपीएफ तारीख 18-4-1980

11–एफ 16(2)–पैन/79–जीपीएफ तारीख 12–6–1980
12. एफ 11(1)–पैन/77–जीपीएफ तारीख 1–10–1980
13. एफ 16(3)–पैन/79–जीपीएफ तारीख 13–10–1980
14. एफ 10(2)–पैन/81–जीपीएफ तारीख 21–12–1981
15 एफ 13(1)–पैन/82–जीपीएफ तारीख 8–9–1982
16 एफ 13(3)–पैन/82–जीपीएफ तारीख 30–4–1983
17. एफ 19(2)–पैन/80–जीपीएफ तारीख 30–4–1983
18. एफ 16(3)–पैन/–77जीपीएफ तारीख 19–5–1983
19. एफ 13(2)/80–पैन तारीख 20–5–1983
20. एफ 19(1)–पैन/83–जीपीएफ तारीख 20–5–1983
21 एफ 20(10)/81–पेंशन यूनिट–जीपीएफ तारीख 30–7–83
22 एफ 13(1)–पैन/84–तारीख 19–3–1984
23. एफ 13/4/84–पी.यू. (जी पी एफ), तारीख 26–2–85
24. एफ 13(1) पैन/85–जीपीएफ तारीख 19–6–1985
25. एफ 13(2)–पैन/85–जीपीएफ तारीख 24–9–1985
26. एफ 13(4)–पैन/85, तारीख 24–1–1986

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

New Delhi, the 27th June, 1986

S.O. 3023.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 :—

1. (1) These Rules may be called the General Provident (Fund (Central Services) Second Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in para 2 of the Fifth Schedule, the following entries shall be inserted at the end but before the first proviso thereunder, namely :—

In respect of Group 'B', 'C' and 'D' Staff of India Meteorological Department, an advance under sub-rule (2) of rule 12 may be sanctioned by the authorities mentioned below :—

(i) Additional Director General of Meteorological (R) Pune.

(ii) Deputy Director General of Meteorological (WF) Pune.

(iii) Deputy Director General of Meteorological (II & S) Pune.

(iv) Director (Agrimet) Pune.

(v) Regional Directors, India Meteorological Department Bombay, Calcutta, Madras, Nagpur & New Delhi.

(vi) Deputy Director General of Meteorological (IP), New Delhi.

(vii) Meteorological-in-charge, CSO, Indian Meteorological Department, Shillong.

(viii) Director Positional Astronomy Centre, India, Meteorological Department, Calcutta".

[No. 13(3)-Pen. 85-G.P.F.]
HAZARA SINGH, Dy. Secy.

Note : General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 were published as S.O. 3060 dated 1-12-1960. The Third reprint (corrected upto 30-11-1978) of the rules was printed in 1979. The rules were subsequently amended vide notification mentioned below :—

1. F. 13(8)|77-EV(B), dated 13-12-1978.
2. F. 13(5)|78-EV(B), dt. 23-4-1979.
3. F. 13(11)|78-EV(B) dt. 30-5-79.
4. F. 13(7)|78-EV(B) dt. 18-6-1979.
5. F. 17(5)|EV(B)|78, dt. 18-6-1979.
6. F. 19(15)-Pen|76(GPF) dt. 9-8-1979.
7. F. 9(2)-EV(B)|Pen|78-GPF dt. 13-11-1979.
8. F. 10(10)-Pen|79-GPF dt. 3-3-1980.
9. F. 20(22)-EV(B)|Pen|79-GPF dt. 18-4-1980.
10. F. 13(6)-Pen|79-GPF dt. 18-4-1980.
11. F. 16(2)-Pen|79-GPF dt. 12-6-1980.
12. F. 11(1)-Pen|77-GPF dt. 1-10-1980.
13. F. 16(3)|Pen|79-GPF dt. 13-10-1980.
14. F. 10(2)-Pen|81-GPF dt. 21-12-1981.
15. F. 13(1)-Pen|GPF dt. 8-9-1982.
16. F. 13(3)-Pen|82-GPF dt. 30-4-1983.
17. F. 19(2)-Pen|80-GPF dt. 10-5-1983.
18. F. 16(3)-Pen|77-GPF dt. 19-5-1983.
19. F. 13(2)|80-Pen|dt. 20-5-1983.
20. F. 19(1)-Pen|83-GPF dt. 20-5-1983.
21. F. 20(10)|81-Pension Unit-GPF dt. 30-7-1983.
22. F. 13(1)-Pen|84 dt. 19-3-1984.
23. F. 13|4|84-P.U. (GPF), dt. 26-2-1985.
24. F. 13(1)-Pen|85 GPF dt. 19-6-1985.
25. F. 13(2)-Pen|85-GPF dt. 24-9-1985.
26. F. 13(4)-Pen|85, dt. 24-1-1986.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1986

आयकर

का. आ. 3024.—इस कार्यालय की दिनांक 19-7-85 की अधिसूचना सं. 6334 (पत्र सं. 203/120/85-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (वैज्ञा/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(I) यह कि राजकोट कैंसर सोसाइटी, राजकोट अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

(II) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

(III) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां, दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी ।

(IV) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगी । आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

संस्था

"राजकोट कैंसर सोसाइटी, राय रोड, राजकोट-360001."

यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं. 6791/फा. सं. 203/32/86-आ. क. नि-II]
के. के. त्रिपाठी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th July, 1986

INCOME-TAX

S.O. 3024.—In continuation of this Office Notification No. 6334 (F. No. 203/120/85-ITA.II) dated 19-7-1985, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Rajkot Cancer Society, Rajkot will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Rajkot Cancer Society, Raiya Road, Rajkot-360001."

This Notification is effective for a period from 1-4-1986 to 31-3-1987.

[No. 6791/F. No. 203/32/86-ITA. II]

K. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1986

का.आ. 3025 :—भारत सरकार के अपर सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/36/86-सी.शु.-VIII, तारीख 19-3-86 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री स्वरूप सिंह, बी-20, गुजरवालां टाउन, पार्ट-II, दिल्ली को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कार्य करने से निवारित किया जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस, आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/36/86-सी.शु.-VIII]

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1986

S.O. 3025.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under Sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/36/86-Cus.-VIII dated 19-3-86 under the said sub-section directing that Shri Sarup Singh, B-20, Gujaranwala Town, Pt. II, Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/36/86-Cus.VIII]

आदेश

का.आ. 3026:—भारत सरकार के अपर सचिव, ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/65/86-सी.शु.-VIII, तारीख 1-4-1986 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री हरी सिंह सुपुत्र श्री चानन सिंह, निवासी गांव डुके, जिला अमृतसर को केन्द्रीय कारागार तिहाड़, नई दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे तस्करी के माल को छिपाने तथा रखने के कार्य में ग्रस्त होने के अन्यथा तस्करी के माल को लाने ले जाने तथा तस्करी माल का व्यापार करने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पंजाब के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/65/86-सी.शु.-VIII]

ORDER

S.O. 3026.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. N. 673/65/86-Cus.VIII dated 1-4-86 under the said sub-section directing that Shri Hari Singh S/o Sh. Channan Singh residing at Village Dooke, Distt. Amritsar, Punjab be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in transporting smuggled goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in concealing or keeping smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Punjab within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/65/86-Cus.VIII]

आदेश

का.आ. 3027.—भारत सरकार के अपर सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण नियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/73/86-सी.शु.- VIII, तारीख 28-4-86 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि गांव व डाकखाना रणबीर सिंह पुरा, जिला जम्मू व कश्मीर के निवासी श्री दुर्गा दास शर्मा को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/73/86-सी.शु.-VIII]

एस. के. चौधरी, अवर सचिव

ORDER

S.O. 3027.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. N. 673|73|86-Cus.VIII dated 28-4-86 under the said sub-section directing that Shri Durga Dass Sharma, residing at Village & P. O. Ranbir Singh Pura, Distt. Jammu, J.&K, be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from smuggling goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, J.&K., Srinagar within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|73|86-Cus.VIII]

S. K. CHOWDHRY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1986

स्टाम्प

का.आ. 3828 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो इण्डस्ट्रीयल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता द्वारा जारी किये जाने वाले पचपन करोड़ रुपये मात्र के मूल्य के प्रामिसरी नोट—9.75%/आई.आर बी.आई. बंधपत्र (12वी श्रृंखला) के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 33/86—स्टाम्प—फा. सं. 33/8/86—वि. क.]

ORDER

New Delhi, the 12th August, 1986

STAMPS

S.O. 3028.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1989 (2 of 1989), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory Notes 9.75% IRBI Bonda (12th Series) to the value of Fifty Five crores rupees only to be issued by the Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta, are chargeable under the said Act.

[No. 33|86-Stamps-F. No. 33|8|86-ST]

का.आ. 3029.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले पैंतीस करोड़ रुपये मात्र के मूल्य के ऋणपत्रों (10.5% ऋणपत्र 1996 XXV श्रृंखला के रूप में वर्णित) के स्वरूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 32/86—स्टाम्प—फा. सं. 33/47/86-वि. क.]

S.O. 3029.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Debentures (described as 10.5% Debentures 1996 XXV series) to the value of Thirty Five crores rupees only to be issue by the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 32|86-Stamps-F. No. 33|47|86-ST]

का.आ. 3030 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैस्चिनन फैब्रिक पोलीग्राफ (इंडिया) लि. बम्बई को सैंतीस हजार पांच सौ रुपये मात्र के समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी की अनुमति देती है, जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र पचास लाख रुपये मूल्य के क्रम संख्या 1 से 50,000 तक के 15%/आरक्षित असम्परिवर्तनीय ऋणपत्रों पर, जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रु. है, स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 30/86-स्टाम्प—फा. सं. 33/41/86—वि. क.]

S.O. 3030.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maschinenfebfarik Polygraph (India) Ltd., Bombay, to pay consolidated stamp duty of rupees Thirty Seven thousand and five hundred only, chargeable on account of the stamp duty on 15% Secured Non-convertible Debentures of the face value of Rs. 100 each bearing Serial Nos. 1 to 50,000 value of rupees Fifty lakhs only, to be issued by the said Company.

[No. 30|86-Stamps-F. No. 33|41|86-ST]

का.आ. 3031 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इंडियन ऑरगैनिक कैमिकल्स, लिमिटेड बम्बई को पांच लाख छः हजार दो सौ पचास रुपये मात्र के समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले छः करोड़ पचहत्तर लाख रुपये के अंकित मूल्य के क्रम संख्या 1 से 6,75,000 वाले 15% आरक्षित विमोच्य असम्परिवर्तनीय ऋणपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 31/86—स्टाम्प—फा. सं. 33/42/86—वि. क.]

बी. आर. मेहमी, अवर सचिव

S.O. 3031.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Indian Organic Chemicals, Limited, Bombay to pay consolidated stamp duty of Five lakhs, six thousand, two hundred and fifty rupees only, chargeable on account of the stamp duty on 15% Secured Redeemable Non-convertible debentures bearing serial Nos. 1 to 6,75,000 of the face value of rupees Six crores and Seventy five lakhs only to be issued by the said company.

[No. 31|86-Stamps-F. No. 33|42|86-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1986

का.आ. 3032.—सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20 जून, 1986 की इस संबंधक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) के प्रशासनिक अधिकारी को उपर्युक्त अधिनियम को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो महाप्रबन्धक बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) के नियंत्रणाधीन सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों तथा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा।

[संख्या एफ. 2 (16)/81-कोइन]

सी. जी. पथरोज, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 13th August, 1986

S.O. 3032.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the Notification of even number dated 20th June 1986, the Central Government hereby appoints the Administrative Officer, Bank Note Press, Dewas (M.P.) to be Estate Officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officer by or under the said Act in respect of the public premises under the control of the General Manager, Bank Note Press, Dewas (M.P.).

[No. F. 2(16)|81-Coin]

C. G. PATHROSE, Under Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1986

का.आ. 3033.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के.पी. शाह को 4-11-85 से संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आजमगढ़ (उ.प्र.) का अध्यक्ष नियुक्त करती है। श्री के.पी. शाह अगला आदेश जारी होने तक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।

[सं. एफ. 2-7/82-आर.आर.बी.]

ब.वा. मीरचन्दानी, निदेशक

(Banking Division)

New Delhi, the 5th August, 1986

S.O. 3033.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. P. Shah as the Chairman of Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh (U.P.) w.e.f. 4-11-1985. Shri K. P. Shah shall hold office as such Chairman until further orders.

[No. F. 2-7|82-RRB]

C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1986

का. आ. 3034.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियमावली 1966 के नियम 10 साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 31 के उपबंध कोंकण प्रान्त सहकारी बैंक लिमिटेड, बम्बई पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिस तक उनका संबंध दिनांक 30 जून, 1985 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन से है।

[एफ. सं. 8-2/86-एसी]

के. पी. पाण्डियन, अवर सचिव

New Delhi, the 19th August, 1986

S.O. 3034.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 31 of the Banking Regulation Act, 1949 (As applicable to Cooperative Societies) read with Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies) Rules 1966, shall not apply to the Konkan Prant Sahakari Bank Ltd. Bombay so far as they relate to the publication of its balance sheet and profit and loss account for the year ended 30 June 1985 together with the auditor's report in a news paper.

[F. No. 8-2/86-AC]

R. P. PANDIAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

कलकत्ता, 28 मई, 1986

अधिसूचना सं० 4/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/1986

का. आ. 3035.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं सी. शुजंगस्वामी, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इसके द्वारा उपरोक्त नियमावली के नियम 173 जी के द्वितीय परंतुक के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक समाहर्ताओं को प्रतिनियुक्त करता हूं जिनका प्रयोग वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, कलकत्ता-1 के अपने सम्बन्धित कार्यक्षेत्र में करेंगे।

[सी सं. IV(16)2-आर आर/86]

सी. शुजंगस्वामी, समाहर्ता

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE

CENTRAL EXCISE

Calcutta, the 28th May, 1986

Notification No. 4/Central Excise/1986

S.O. 3035.—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I C. Bhujangaswamy, Collector of Central Excise hereby delegate the powers under the second proviso to rule 173F of the said rules to the Assistant Collectors of Central Excise to be exercised within their respective jurisdiction in the Collectorate of Central Excise, Calcutta-1.

[C. No. IV(16)2-RR/86/2081]

C. BHUJANGASWAMY, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1986

का. आ. 3036—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "सेफटी रेजर ब्लेड" के संबंध में भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण चिह्न को मान्यता देने का प्रस्ताव यह घोषित करने के लिए करती है कि जिन "सेफटी रेजर ब्लेडों" पर ऐसे चिह्न लगाए या चिपकाए जाएं वे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे जाएंगे ;

और केन्द्रीय सरकार ने उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों कि बाबत कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात-निरीक्षण परिषद, 11 वी मंजिल, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस आदेश में "सेफटी रेजर ब्लेड" से शीघ्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले दोहरी धार वाले सेफटी रेजर ब्लेड अभिप्रेत हैं।

[फाइल सं. 6(15)/86-ई आइ एंड ई पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 6th September, 1986

S.O. 3036.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), proposes to recognise the Indian Standards Institution, Certification mark in relation to Safety Razor Blades for the purpose of denoting that where 'Safety Razor Blades' are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the Standard Specifications applicable thereto under the said Act ;

And whereas the Central Government forwarded the same to the Export Inspection (Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within fortyfive days of publication of this notification in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 11th floor, Pragati Tower, 26, Rajendra Palace, New Delhi-110008.

Explanation : In this Order "Safety Razor Blades" shall mean double edged safety razor blades used for shaving.

[F. No. 6(15)/86-EI&EP]

आदेश

का.आ. 3037.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी-नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत में निर्यात व्यापार के विकास के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने प्रेशर कुकरों से संबंधित आदेश सं. का.आ. 72 तारीख 1 जनवरी, 1983 में नीचे विनिर्दिष्ट ढंग से संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 11 वी मंजिल, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) उक्त आदेश में खंड (4) के अंतर्गत अन्त में आने वाले "निर्यात योग्य है", शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"या उस पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त मुहर या चिन्ह चिपकाया गया है।"

[फाइल सं. 6(11)/86—ईआई एंड ईपी]

ORDER

S.O. 3037.—Whereas the Central Government is of the opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the order of Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 72 dated the 1st January, 1983 regarding pressure cookers in the manner specified below for the development of the Export Trade of India;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Cen-

tral Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within forty five days from the date of the publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, 11th floor, Pragati Tower, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) In the said Order, under clause 1(4) after the word 'exportworthy' occuring at the end, the following words shall be added, namely:—

"or is affixed a seal or mark recognised by the Central Government under section 8 of the said Act".

[F. No. 6(11)/86-EI&EP]

का.आ. 3038—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेशर कुकरों के संबंध में भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव, यह घोषित करने के प्रयोजन के लिए करती है कि जिन प्रेशर कुकरों पर ऐसे चिन्ह लगाए या चिपकाए गए है कि वे उक्त अधिनियम् के अंतर्गत लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे जाएंगे ;

और केन्द्रीय सरकार ने उसे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों को, उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावो के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 11वी मंजिल, प्रगति टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में "प्रेशर कुकर" से ऐसे प्रेशर कुकिंग बर्तन अभिप्रेत हैं जिनकी क्षमता 4 से 22 लिटर है और जो 1.0 के जी एफ/सीएम 2 के कार्यकारी वाष्प दबाव को बनाए रखने वाले बाह्य ताप स्रोतों पर उपयोग के लिए है ।

[फा.सं. 6(11)/86-ईआई एंड ईपी]

S.O. 3038.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) proposes to recognise the Indian Standards Institution Certification mark in relation to Pressure Cookers for the purpose of denoting that where pressure cookers are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable there under the said Act;

And whereas the Central Government forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1984;

Now, therefore in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of pubication of this notification in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 11th floor, Pragati Tower, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

EXPLANATION.—In this notification, "Pressure Cookers" means any pressure cooking vessel of capacity from 4 litres upto and including 22 litres for use with external heat sources capable of maintaining working steam pressure of 1.0kgf/cm.

[F. No. 6(11)/86-EI&EP]

आदेश

का.आ. 3039—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए यह आवश्यक तथा समीचीन है कि चश्मा फ्रेमों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रगति टावर, 11 वीं मंजिल, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि चश्मा फ्रेमों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ;

(2) निम्नलिखित को चश्मा फ्रेमों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना, अर्थात्:—

(क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानक ; या

(ख) चश्मा फ्रेमों के लिए निर्यात संविदा में निर्यातकर्ता द्वारा स्वीकृत विनिर्देशों के रूप में घोषित विनिर्देश परन्तु यह तब जब कि वे उपबंध-1 में दिए गए विनिर्देशों से निम्न न हो ।

टिप्पण :—(i) जब निर्यात संविदा में, ब्यौरेवार तकनीकी अपेक्षाएं उपवर्णित नहीं हों या केवल नमूनों पर आधारित हो, तो निर्यातकर्ता लिखित विनिर्देश देगा ।

(ii) परीक्षण की पद्धतियां राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी ।

(3) इस आदेश के उपाबंध-2 में उपवर्णित चश्मा फ्रेमों निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व चश्मा फ्रेमों को लागू किया जाएगा ।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे चश्मा फ्रेमों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि चश्मा फ्रेम क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते है, तथा निर्यात योग्य हैं ।

3 इस आदेश की कोई भी बात भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा भावी खेपाओं को 500 रु. से अधिक के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के चश्मा फ्रेमों के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी ।

4. इस आदेश में "चश्मा फ्रेम" से निम्नलिखित में से कोई भी अभिप्रेत है :—

(i) सैल्यूलोस ऐसीटेट सैल्यूलोस नाईट्रेट और अन्य प्लास्टिक शीटों से बनाए गए फ्रेम ;

(ii) ढाले गए प्लास्टिक फ्रेम ;

(iii) धातु के फ्रेम ;

(iv) धातु और प्लास्टिक के मिले जुले फ्रेम ।

उपाबंध 1

चश्मा फ्रेमों के लिए विनिर्देश :—

1. कारीगरी और फिनीश :—

(i) फ्रेम दोषों, धब्बों और चटखनों तथा विनिर्माण त्रुटियों से मुक्त होंगे ।

(ii) सभी तेज किनारे और कोने, रेती चिन्ह तथा खुरदरापन पॉलिश करने से पहले हटा दिए जाएंगे ।

(iii) जोड़ सफाई से तथा मजबूती से फिट तथा पालिस किए जाएंगे और घिसाई या अन्य कारणों से हुआ कोई चिन्ह उन पर दिखाई नहीं देना चाहिए ।

(iv) रिवट इस प्रकार लगाए जाएंगे ताकि न तो तार और न ही आरों और की सामग्री विभाजित हो या चटके या क्षति-ग्रस्त हो ।

(v) पेंचों के शीर्ष अक्षतिग्रस्त होंगे ।

(vi) अग्रभाग और साइड लेंग के साथ सफाई से लगाई जाएंगी ।

2. विमाएं :—फ्रेम की विमाएं निर्यात संविदा के अनुसार होंगी । एक साइड की लम्बाई ± 1 मि.मी. की सहिष्णुता के अधीन होगी और उसे जोड़ों से साइड के मोड़ तक नापा जाएगा । मोटाई को छोड़कर अन्य सभी विमाएं ± 0.5 मि.मी. की सहिष्णुता के अधीन होंगी ।

3. अन्य अपेक्षाएं :—

(i) प्लास्टिक फ्रेमों की लगों के शेरों को छोड़कर अग्रभाग की मोटाई कहीं भी 3.4 मि.मी. से कम नहीं होगी ।

(ii) फ्रेमों की अनुलम्बीय प्लान में ब्रिज की मोटाई, तथा सहिष्णुता निर्यातकर्ता द्वारा यथा घोषित निर्यात संविदा के अनुसार होगी ।

(iii) कमानियां आकार और आकृति से मेल खानी चाहिए ।

(iv) कमानियों की रेडियल मोटाई 1.5 मि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए ।

(v) खांचे यू या वी आकार के होंगे, उचित स्थान पर होंगे तथा सुअवस्थित रूप से बनाए हुए होंगे और उनकी गहराई 0.6 ± 0.1 मि. मी. होगी । खांचों और कमानियों का भीतरी भाग एक सार रूप से फिनिश होगा ।

(vi) पैड समान ऊंचाई के होंगे और ऊंचाई फ्रेम की आधारित रेखा के सापेक्ष होगी । यदि पैड अग्र भाग के साथ संयुक्त नहीं है तो वे फ्रेम पर सफाई से स्थायी रूप से जोड़े जाएंगे ।

उपाबंध 2

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (चश्मा फ्रेम निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 है ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित तथा मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) चश्मा फ्रेम से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है :—

(i) सैल्यूलोस ऐसीटेट, सैल्यूलोस नाईट्रेट, और अन्य प्लास्टिक शीटों से बनाए गए फ्रेम ।

(ii) ढाले गए प्लास्टिक फ्रेम ।

(iii) धातु के फ्रेम ।

(iv) धातु और प्लास्टिक के मिले-जुले फ्रेम ।

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात किए जाने वाले चश्मा फ्रेमों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि चश्मों के फ्रेम अधिनियम, की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, अर्थात्, यह

या तो

(i) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पादों का विनिर्माण उत्पादन के दौरान निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली यूनिटों के संबंध में इस अधिसूचना के उपाबंध-क में यथा-विनिर्दिष्ट क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली उत्पादन के दौरान अपनाकर किया गया है ;

या

(ii) निरीक्षण की परेषणानुसार प्रणाली के अधीन आने वाली यूनिटों के संबंध में, इस अधिसूचना के उपाबंध-ख में विनिर्दिष्ट रीति से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया जाएगा ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) चश्मा फ्रेमों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, निर्यात संविदा या आदेश की प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए, अभिकरण को लिखित संसूचित करेगा जिससे कि अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके ।

(2) ऐसे चश्मा फ्रेमों के निर्यात के लिए जिनका विनिर्माण उपाबंध-क में अधिकथित उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण अपना करके, और परिषद् के द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा यह न्याय निर्णीत करके कि उत्पादन के दौरान यूनिट में पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ढिलें है, किया गया है निर्यातकर्ता उप नियम (1) में उल्लिखित संसूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित चश्मा फ्रेमों के परेषण का विनिर्माण उपाबंध-क में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों को अपनाकर किया गया है और परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(3) निर्यातकर्ता अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी प्रस्तुत करेगा ।

(4) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक संसूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम पांच दिन पूर्व दी जाएगी जबकि उप नियम (2) के अधीन घोषणा सहित संसूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी ।

(5) उप नियम (1) के अधीन संसूचना और उप नियम (2) के अधीन घोषणा के, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर अभिकरण —

(क) (i) अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता के उपाबंध-क में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है और अधिनियम, की धारा 7 के अंतर्गत

मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के संबंध में परिषद् या अभिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हो, का पालन किया है, तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि चश्मा फ्रेमों का परेषण निर्यात योग्य है ।

(ii) जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है वहां परेषण का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन और या निरीक्षण यदि आवश्यक हो, अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है ।

(iii) अभिकरण निर्यात के लिए आशयित कुछ परेषणों की स्थल पर जांच करेगा और विनिर्माण एककों द्वारा अपनाई गई उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता का सत्यापन करने के लिए नियमित अंतरालों पर विनिर्माण एककों में जाएगा ।

(iv) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक के विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग नहीं किया है या परिषद् या अभिकरण की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया है तो यह घोषणा कर दी जाएगी कि यूनिट के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलें नहीं है और ऐसे मामलों में यदि यूनिट ऐसा चाहे तो उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता बनाए रखने के अधिनिर्णय के लिए फिर से आवेदन करेगा ।

(ख) जहां निर्यातकर्ता ने उप-नियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है वहां अपना यह समाधान कर लेने पर कि चश्मे के फ्रेम का परेषण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, उपाबंध-ख में यथाकथित किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ऐसा निरीक्षण करने के पांच दिन के भीतर यह घोषित करते हुए, प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि चश्मे के फ्रेमों का परेषण निर्यात योग्य है ;

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है वहां वह यह घोषित करते हुए कि चश्मे के फ्रेमों का परेषण निर्यात योग्य है, प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना पांच दिनों के भीतर निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित दी जाएगी ।

(ग) (i) उस दशा में जहां विनिर्माता उप नियम-5 (क) के अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उप नियम-5(ख) के अधीन निरीक्षण नहीं किया गया है वहां अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् तुरन्त ही परेषण में से पैकेजों को इस रीति से मुहरबंद करेगा कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मुहरबंद पैकेजों में फेरबदल नहीं की जा सकती है ।

(ii) परेषण की अस्वीकृति की दशा में यदि निर्यातकर्ता चाहे तो परेषण अभिकरण द्वारा मुहरबंद नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

5. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो (क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर पर, या (ख) उन परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह तब जब कि वहां प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो ।

6. निरीक्षण फीस :—निर्यात-कर्ता अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नानुसार देगा :—

(i) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण योजना के अधीन, निर्यात के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से,

(ii) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात करने के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से ।

7. अपील :—(1) नियम 4 के उप नियम 5 के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करने के व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पैनल को, जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा ।

(2) पैनल के विशेषज्ञों की कुल सदस्यता के दो तिहाई सदस्य प्रशासकीय व्यक्ति होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

उपाबंध—क

क्वालिटी नियंत्रण :—

विनिर्माता चश्मे के फ्रेमों का क्वालिटी नियंत्रण नीचे अधिकथित रूप में उत्पादों के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर तथा उससे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रण के स्तरों सहित निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए करेंगा ।

(i) क्रय की गई सामग्री तथा संघटक नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री या संघटकों की विशेषताओं तथा उनकी स्वीकार्य विमाओं को समाविष्ट करते हुए क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो सब अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए, उत्पादक या परीक्षण प्रमाण-पत्र होगा अथवा ऐसे परीक्षण प्रमाण-पत्र के अभाव में क्रय विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता की जांच करने के लिए प्रत्येक लौट में से नमूनों की नियमित जांच की जाएगी । उत्पादनकर्त्ता के परीक्षण प्रमाणपत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए दस परेषणों में से कम से कम एक परेषण की जांच की जाएगी ।

(ग) आने वाले परेषणों का निरीक्षण और पुनर्निरीक्षण सांख्यिकीय नमूना प्लायन के आधार पर क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा ।

(घ) निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात्, दोषों को उचित रूप से दूर करने और निपटाने के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे ।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण :—

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए विनिर्माता द्वारा कार्यकारी प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रिया नियंत्रण के लिए उपस्करों या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे ।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :—

(क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के विनर्माता के पास पर्याप्त सुविधाएं होंगी । इसके लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे ।

(ख) चश्मा फ्रेमों के प्रत्येक भाग की अधिकथित निरीक्षण जांच सूची के अनुसार जांच की जाएगी ।

(iv) माप संबंधी नियंत्रण.—उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त मापकों तथा उपकरणों की कालिक जांच या उनका अंश संशोधन किया जाएगा तथा अभिलेख वृत्तकार्ड के रूप में रखे जाएंगे ।

(v) परिरक्षण नियंत्रण :—

(क) उत्पाद को मौसमी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माता द्वारा समुचित विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान उत्पाद को अच्छी प्रकार से परिरक्षित रखा जाएगा ।

(vi) पैकिंग नियंत्रण :— यातायात बाधा और वातावरण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्यात पैकिंग के लिए विस्तृत विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा ।

अनुसूची

उत्पाद के लिए नियंत्रण के स्तर

[उपाबंध-क का उप-पैरा (iii) देखें]

क्रम सं.	विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूनों की सं	आवृत्ति	टिप्पण
1	2	3	4	5	6
1.	कारीगरी और फिनिश	मानक विनिर्देशों के अनुसार	100 प्रतिशत	—	—
2.	विमाएं और सहिष्णुता	यथोक्त	उत्पादन का 10%	बैचवार	—
3.	प्रकोष्ठिक मोटाई सहित मोटाई	यथोक्त	5%	बैचवार	—
4.	खांचों की गहराई	यथोक्त	उत्पादन का 5%	बैचवार	—
5.	पैकिंग और चिह्नन	यथोक्त	पांच नमूनों की जांच की जाएगी	प्रत्येक एक घंटे बाद	—
6.	कोई अन्य अपेक्षा	यथोक्त	अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर निर्धारित की जाएंगी ।	बैचवार	—

उपाबंध-ख

1. परेषणानुसार निरीक्षण :—

1.1. चश्मा फ्रेमों के परेषण का निरीक्षण और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि परेषण अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

1.2 नमूना लेने के संबंध में संविदात्मक विनिर्देशों में से कोई विशिष्ट अनुबंध न होने की दशा में वह नीचे दी गई सारणी में अधिकथित के अनुसार लागू होगा ।

सारणी

नमूनों का मापदंड

नमूनों का मापदंड और अनुज्ञेय दोषों की संख्या

(खंड - 5.1.1)

लॉट आकार	चुने जाने वाले नमूनों की संख्या	अनुज्ञेय दोषों की संख्या
एन	एम	
(1)	(2)	(3)
100 तक	5	0
100 से 150	8	1
151 से 300	13	1
301 से 500	20	2
501 से 1000	32	3
1001 से 3000	50	5
3001 और अधिक	80	7

नोट :— एकल परेषण में एक ही प्रकार के और एक ही अवस्था में विनिर्मित चश्मा फ्रेमों को एक लॉट बनाने के लिए एक साथ एकत्रित किया जाएगा ।

1.3 उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रत्येक डिब्बे में से या इच्छित रूप से चुने गए, सारणी के अनुसार प्रत्येक डिब्बे में से चश्मे के फ्रेम की उपयुक्त संख्या सूची के अनुसार होगी ।

1.4 लॉट में से चुने जाने वाले फ्रेमों की संख्या लॉट के आकार पर निर्भर होगी, और सारणी के स्तम्भ-1 और 2 के अनुसार होगी ।

1.5 ये फ्रेम लॉट में से या इच्छिक रूप से चुने जाएंगे । इस उद्देश्य के लिए पैकेटों की संख्या सूची के स्तम्भ-2 के रूप के समान होगी, जो पहले वितरण परेषणों के विभिन्न स्थानों से चुनी जाएगी और जो पैकेट चुना जाएगा एक फ्रेम या दृष्टिक होगा ।

1.6 परीक्षणों की संख्या — सारणी के स्तम्भ-2 से चुने गए सभी फ्रेमों का निरीक्षण मानक के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा । वह फ्रेम जो उनमें से किसी एक या अधिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा त्रुटिपूर्ण कहलाएगा ।

1.7 अनुरूपता का मापदंड — लॉट को इस विनिर्देश की अपेक्षाओं के अनुरूप तब माना जाएगा जब त्रुटिपूर्ण फ्रेमों की कुल संख्या सारणी के स्तम्भ में दी गई संख्या से अधिक नहीं है अन्यथा नहीं ।

[फाइल सं. 6(9)/86—ईआई एंड ई पी]

एन. एस. हरिहरन, निदेशक

ORDER

New Delhi the 6th September, 1986

S.O. 3039.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government after consulting the Export Inspection Council is of opinion that it is necessary and expedient for the development of the export trade of India, that spectacles frames should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the persons likely to be affected thereby;

2. Notice is hereby given that any person desiring to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, Pragati Tower (11th floor), 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that spectacles frames shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To recognise—

(a) the national and international standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council; or

(b) the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications in the export contract for the spectacles frames provided the same are not below the specifications as set out in Annexure I;

as the standard specifications for the said spectacles frames.

NOTES :

(i) When the export contract does not indicate detailed technical requirements or is based only on samples, the exporter shall furnish a written specification;

(ii) Methods of tests will be as per national standards;

(3) To specify the type of quality control and inspection in accordancec with the draft Export of Spectacles Frames (Quality Control and Inspection) Rules, 1986 set out in Annexure II to this order as the eype of quality control and inspection which shall be applied to such spectacles frames, prior to export;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such spectacles frames unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established or recognised by the Central Government under section 7 of the said Act to the effect that the spectacles frames satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of spectacles frames not exceeding Rs. 500 in F.O.B. value to the prospective buyers.

4. In this order 'spectacle frames' means any of the following :—

(i) Frames made from cellulose acetate, cellulose nitrate and other plastic sheets ;

(ii) moulded plastic frames ;

(iii) metallic frames ;

(iv) Combination frames of metals and plastics.

ANNEXURE—I

Specifications for spectacle frames

1. Workmanship and finish :—

(i) The frames shall be free from faults, blemishes and cracks and manufacturing defects.

(ii) All sharp edges and cornners, file marks and roughness shall be removed before polishing.

(iii) The joints shall be neatly and securely fitted and polished and shall show no signs of damage through filling or other causes.

(iv) The rivets shall be fixed in such a manner that neither the wire nor the surrounding meterial shall be split, cracked or damaged.

(v) The screw heads shall be undamaged.

(vi) The front and the sides shall match neatly with the lug.

2. Dimensions :—The dimensions of frames shall be as per export contract. The side length dimension shall be subject to a tolerance of ± 1 mm and shall be measured from the joint upto the bend of the side. All other dimensions excepting the thickness shall be subject to a tolerance of ± 0.5 mm.

3. Other requirements :—

(i) The thickness of the front excluding the ends of the lugs of the plastic frames, shall be nowhere less than 3.4 mm.

(ii) The thickness of the bridge in the vertical place of the frames shall be as per export contract as declared by the exporter together with tolerance given therein.

(iii) The rims shall match for shape and size.

(iv) Radial thickness of rims shall be not less than 1.5 mm.

(v) Grooves shall be u or v shaped, suitably placed and systematically formed, and shall be of 0.6 ± 0.1 mm depth. The grooves and the inner surfaces of the rims shall be smoothly finished.

(vi) Pads shall be at the same height relative to the datum line of the frame. In case the pads are not integral with the front, they shall be neatly and firmly cemented to the frame.

ANNEXUE—II

Dramt rule proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Export of Spectacle Frames (Quality Control and Inspection) Rules, 1986.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Agency" means any one of the agencies established or recognised under section 7 of the Act.

(c) "Council" means Export Inspection Counncil established under section 3 of the Act ;

(d) "Spectacle Frames" means any of the following :—

(i) frames made from cellulose acetate, cellulose nitrate and other plastic sheets.

(ii) moulded plastic frames.

(iii) metallic frames.

(iv) combination frames of metals and plastics.

(e) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules.

3. Basis of Inspection.—Inspection of spectacle frames for export shall be carried out with a view to ensuring that the spectacle frames conform to the specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act, that is to say ;

either

(i) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Appendix-A to this notification. in respect of units coming under in process quality control system of inspection;

(ii) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Appendix-B to this notification in respect of units coming under consignmentwise system of inspection.

4. Procedure of inspection .—(1) An exporter intending to export a consignment of spectacle frames shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specification alongwith a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordannce with rule 3;

(2) For export of spectacle frames manufactured by exercising in process quality control as laid down in Appendix-A and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by a panel of Experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also furnish alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of spectacle frames intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Appendix-A and that the consignment conforms to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) shall be given not less than five days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, while in the case of intimation alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2) the agency—

(a) (i) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised quality controls as laid down in Appendix-A and followed the instructions if any issued by the Council or Agency in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised under section 6 of the Act shall within three days issue a certificate declaring the consignment of spectacle frames as exportworthy.

(ii) in case where the manufacturer is not the exporter, the consignment shall be physically verified and such verification and or inspection if necessary shall be carried out by the Agency to ensure that the above conditions are complied with

(iii) the Agency shall carry out the spot-check of some of the consignments meant for export and also visit the manufacturing unit at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by the unit.

(iv) If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council or Agency, the unit shall be declared as not having adequate in process quality control drills and in such cases, the unit if it so desires shall apply afresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control had been exercised, on satisfying itself that the consignment of spectacle frames conforms to the standard specification recognised under section 6 of the Act, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Appendix-B shall within five days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of spectacle frames as exportworthy;

Provided that where the Agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of spectacle frames as exportworthy and shall communicate such refusal within five days to the exporter alongwith the reason thereof.

(a) (i) In case where the manufacture is not the exporter under sub-rule 5(a) or consignment is inspected under sub-rule (5)(b), the Agency shall immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed package cannot be tampered with.

(ii) In case of rejecting of the consignment, if the exporter so desires the consignment may not be sealed by the Agency but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such product, or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection Fee.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :—

(i) For exports under in-process quality control (IPQC) scheme, at the rate of 0.2 per cent of the Free on Board value (F.O.B.)

(ii) For exports under consignmentwise inspection as the rate of 0.4 per cent of the Fee on Board value (F.O.B.).

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven person as may be constituted by the Central Government.

(2) The panel of experts shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership.

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

APPENDIX-A

Quality Control

The quality control of spectacle frames shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the products as laid down below, together with the levels of controls as set out in the Schedule- appended hereto.

(i) Bought-out materials and components control

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials of components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerance.

(b) The accepted consignment shall be either accompanied by a product's test certificate corroborating the requirement of the purchase specifications or in the absence of such test certificates, samples from each lot shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificates shall be counter checked at least once in ten consignments to verify the correctness.

(c) The incoming consignments shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plans.

(d) After inspection and tests are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

(ii) Process Control

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for various processes of manufacture.

(b) Equipment or instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specification.

(c) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls exercised during the process of manufacture.

(iii) Product Control

(a) The manufacturer shall have adequate testing facilities to test the product as per the standard specifications. Adequate records thereof shall also be maintained.

(b) Each and every assembly of spectacle frames shall be checked against a laid down inspection check list.

(iv) Metrological Control

Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked/calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

(v) Preservation Control -

(a) Detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

(vi) Packing control

Detailed specifications shall be laid down for export packaging taking into account the transit hazards and atmospheric conditions. The same shall be followed rigidly.

THE SCHEDULE

LEVELS OF CONTROL FOR PRODUCTS

(See sub-paragraph (iii) of Appendix-A)

Sl. No.	Characteristics	Requirements	No. of samples	Frequency	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Workmanship and Finish	As per standard specification	100%	—	—
2.	Dimensions with tolerances	-do-	10% of the production	Batchwise	—
3.	Thickness including radial thickness.	-do-	5%	Batchwise	—
4.	Depth of the grooves	-do-	5% of the production	Batchwise	—
5.	Packing and Marking	-do-	5 samples to be tested.	After every one hour.	—
6.	Any other requirement	-do-	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Batchwise	—

APPENDIX-B

1. Consignmentwise Inspection:

1.1 The consignment of Spectacle Frames shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the consignment to the standard specification recognised under section 6 of the Act.

1.2 In the absence of specific stipulation in the contractual specification as regards sampling criteria, the same laid down in the Table given below shall become applicable.

THE TABLE

SCALE OF SAMPLING

SCALE OF SAMPLING AND PERMISSIBLE NUMBER OF DEFECTIVES

(Clause 5.1.1)

Lot Size	Number of Samples to be selected	Permissible number of Defectives
N	n	
(1)	(2)	(3)
Upto 100	5	0
101 to 150	8	1
151 to 300	13	1
301 to 500	20	2
501 to 1000	32	3
1001 to 3000	50	5
4001 and above	80	7

LOT : In a single consignment all the spectacle frames of the same type and manufactured under similar conditions shall be grouped together to constitute a lot.

1.3 From each of the cartons selected at random as per Table above, selected at random app. equal number of pieces of Spectacle Frames from each of the cartons in accordance with Table.

1.4 The number of frames to be selected from the lot shall depend upon the size of the lot and shall be in accordance with col. 1 and 2 of Table.

1.5 These frames shall be selected at random from the lot. For this purpose, a number of packets equal to as given in col. 2 of Table shall first be chosen from different places of the delivery consignment and from each of the packets so chosen, one frame shall be selected at random.

1.6 Number of Tests.—All the frames selected as in col. 2 of Table shall be inspected for all the requirements specified in this standard. A frame failing to satisfy any one or more of these requirements shall be regarded as defective.

1.7 Criteria for conformity—A lot shall be considered as conforming to the requirements of this specification if the total number of defective frames in the sample does not exceed the number given in col. 3 of Table otherwise not.

[F. No. 6(9)|85 EJ&EP]

N. S. HARIHARAN, Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

(सी जी-3 अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

का. आ. 3040.—मै. साकेत कैन्स प्रा. लि., 7, शक्ति आदेनवाला रोड, माटंगा, बम्बई-400019 को मुक्त विदेशी मुद्रा के अंतर्गत 1980 में निर्मित 36"×29" माप की एक निप्पम टाइप बी आर सैमी आटोमैटिक मैटल डैकोरेटिंग प्रैस (पुरानी) के आयात के लिए 3,74,300 रु. (तीन लाख, चौहत्तर हजार तथा तीन सौ रुपये मात्र) (यू. एस डालर 30,000) का आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/20982 दिनांक 10-5-85 जारी किया गया था। फर्म ने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क तथा मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी किए जाने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन तथा मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई या अस्थानस्थ हो गई हैं। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति को किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजिकृत नहीं करवाया गया था तथा इस प्रकार सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारक ने विशेष मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टेम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं, तदनुसार संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2098266 दिनांक 10-5-85 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रतियां फर्म द्वारा खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उप-धारा 9(सीसी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं. साकेत कैन्स प्रा. लि. बम्बई को जारी आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2098266 दिनांक 10-5-85 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन एवं मुद्राविनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति को अलग से जारी किया जा रहा है।

[फा० सं० सीजी-3/1312/48/84-85]

आर० एस० ए० लुइस,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

(C.G. III Section)

ORDER

New Delhi, the 20th August, 1986

S.O. 3040.—M|s. Saket Cans Pvt. Ltd., 7, Shakti Adenwalla Road, Matunga, Bombay-400019 were granted an Import Licence No. P/CG/2098266 dated 10-5-85 for Rs. 3,74,300 (Rupees Three lakhs seventyfour thousand and three hundred only) (US Dollar 30,000) for import of One No. NIPPON Type BR Semi Automatic Metal Decorating Press size 36 inch x 29 inch (Secondhand) manufactured in 1980 under free foreign exchange. The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs & Exchange Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes and Exchange Control copy of the licence has been lost or misplaced. It has furhter been stated that the Customs purposes and Exchange Control copy of the licence was not registered with any Customs authority and as such the value of Customs purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Special Metropolitan Magistrate, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs purposes and Exchange Control copy of import license No. P|CG|2098266 dated 10-5-85 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes and Exchange Control copy of import license No. P|CG|2098266 dated 10-5-85 issued to M|s. Saket Cans Pvt. Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes and Exchange control copy of the said licence is being issued to tre party separately.

[F. No. CG. III/1312|48/84-85]

R. S. A. LOUIS, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1986

का.आ. 3041.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस-ई-यू से सोथासण -54 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस.ई.यू.से एस.ओ.बी. 54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
जगुदन	963	0	02	40
	961	0	06	00
	962	0	08	04
	957	0	09	84
	956	0	10	32
	950	0	08	40
	954	0	06	60
	953	0	10	08

[सं.O-12016/132/86-ओ.एन.जी डी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 13th August, 1986

S.O. 3041.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SEU to Sobhasan-54 in Gujarat State pipeline should be laid down by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SEU to SOB-54

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Jagudan	963	0	02	40
	961	0	06	00
	962	0	08	04
	957	0	09	84
	956	0	10	32
	950	0	08	40
	954	0	06	60
	953	0	10	08

[No. O-12016/132/86-ONG D4]

का.आ. 3042.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डभगा जी.सी.एस. से सरसवनी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाइ जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना अनावश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी का मार्फत।

अनुसूची

डभगा जी.सी.एस. से सरसवनी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बडोदरा तालुका : पादरा

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
साधी	478	0	04	40
	710	0	02	40
	709	0	06	00
	705	0	12	84
	699	0	00	48
	700	0	03	36
	696	0	06	08
	689	0	04	48
	690	0	05	20
	687	0	00	80
	2379	0	04	16
	काटट्रैक	0	00	48
	553	0	08	00
	558	0	06	40
	1837	0	04	80
	1838	0	02	00
	1839	0	04	80
	1842	0	06	48
	1775	0	04	48
	1774	0	06	32
	1767	0	06	40
	1715	0	00	30
	1722	0	02	00
	1706	0	02	00
	1705	0	04	00
	1704	0	07	24
	1703	0	02	36
	1702	0	04	64
	1701	0	09	60

[सं. O-12016/129/86-ओ एन जी डी-4]

New Delhi, the 13th August, 1986

S.O. 3042.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dabka GCS to Sarswani in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Dabka GCS to Sarswani
State : Gujarat District : Barod Taluka : Padara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Sadhi	478	0	04	40
	710	0	02	40
	709	0	06	00
	705	0	12	84
	699	0	00	48
	700	0	03	36
	696	0	06	08
	689	0	04	48
	690	0	05	20
	687	0	00	80
	2379	0	04	16
	Cart track	0	00	48
	553	0	08	00
	558	0	06	40
	1837	0	04	80
	1838	0	02	00
	1839	0	04	80
	1842	0	06	48
	1775	0	04	48
	1774	0	06	32
	1767	0	06	40
	1715	0	00	30
	1722	0	02	00
	1706	0	02	00
	1705	0	04	00
	1704	0	07	24
	1703	0	02	36
	1702	0	04	64
	1701	0	09	60

[No. 12016/129/86-ONG-D-4]

663 GI/86—3.

का. आ. 3043.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नंदासन-1 से ई.पी.एस कैयाल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

नंदासन-1 से ई.पी.एस. कैयाल तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य गुजरात जिला मेहसाना तालुका कड़ी

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कईयाल	534	0	02	28
	535	0	09	48
	कच्चा ट्रैक	0	01	20
	548	0	06	84
	548	0	04	20
	550	0	03	80
	कार्ट ट्रैक	0	10	44
	825	0	12	60

[सं. O-12016/130/86-ओ एन जी डी 4]

S.O. 3043.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Nandasan-1 to EPS Kaiyal in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE,

Pipeline from Nandasan-I to EPS Kaiyal

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kaiyal	534	0	02	28
	535	0	09	48
	Cart track	0	01	20
	548	0	06	84
	548	0	04	20
	550	0	03	80
	Cart track	0	10	44
	825	0	12	60

[No. O-12016/130/86-ONG-D4)]

का.आ. 3044:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐस ई 4 से ऐस ओ बी 54 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ऐस ई 4 से ऐस ओ बी 54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला व तालुका मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
मेवड	237	0	38	28
	406	0	12	24
	403	0	10	08
	402	0	08	64
	400	0	05	30

[सं. O-12016/131/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3044.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SE4 to SOB54 in Gujarat state pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SE 4 to SOB-54

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Meward	237	0	38	28
	406	0	12	24
	403	0	10	08
	402	0	08	64
	400	0	05	30

[No. O-12016/131/86-ONG-D4]

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

का. आ. 3045:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन. के. एफ. आई. से ऐन. के. ई. ऐफ. से ऐन. के. ई. जेड. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ऐन. के. ऐफ. वाई. से ऐन. के. ई. ऐफ. से ऐन. के. ई. जेड. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य :— गुजरात जिला :—व तालुका :—मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मेहमदपुरा	366/पी	0	03	67
	367	0	05	85
	352	0	00	60
	350	0	10	14
	349	0	06	06
	348	0	06	72
	347	0	07	68
	346	0	08	34

[सं. O-12016/133/86-ओ. एन जी.-डी-4]

New Delhi, the 14th August, 1986

S.O. 3045.—Whereas it a appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKFY to NKEF to NKEZ in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed heerto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKFY to NKEF to NKEZ

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Memadpura	366/P	0	03	67
	367	0	05	85
	352	0	00	60
	350	0	10	14
	349	0	06	06
	348	0	06	72
	347	0	07	68
	346	0	08	34

[No. O-12016/133/86-ONG-D4]

का. आ. 3046:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन. के. ऐफ. वाई. से ऐन. के. ई. जेड. से ऐन. के. ई. ऐफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

ऐन. के. ऐफ. वाई. से ऐन. के. ई. जेड. से ऐन. के. ई. ऐफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य :—गुजरात जिला :—मेहसाना तालुका :—कडी

गांव	सं. नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालासन	159/2	0	05	23
	159/3	0	02	76
	157/1	0	04	29
	157/2	0	08	16
	157/3	0	02	88
	154/3	0	07	98
	154/1	0	08	16

[सं. O-12016/134/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3046.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKFY to NKFZ to NKEF in Gujarat State pipeline should be laid down by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKFY to NKEZ to NKEF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chalasan	159/2	0	05	23
	159/3	0	02	76
	157/1	0	04	29
	157/2	0	08	16
	157/3	0	02	88
	154/3	0	07	98
	154/1	0	08	16

[No. O-12016/134/86-ONG-D-4]

का. आ. 3047:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐस. ऐन. ऐ. बी. से ऐस. ऐन. ऐ. ऐफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा -9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

ऐस. ऐन. ऐ. बी. से ऐस. ऐन. ऐन ऐफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य :—गुजरात जिला :—व तालुका :—मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	एयर	सेंटीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कसलपुरा	494	0	06	80
	492	0	01	00
	493	0	10	70
	453	0	13	00

[सं. O-12016/135/86-ओ. एन. जी.-डी.-4]

S.O. 3047.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAB to SNAF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNAB to SNAF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kasalpura	494	0	06	80
	492	0	01	00
	493	0	10	70
	453	0	13	00

[No. O-12016/135/86-ONG-D-4]

का. आ. 3048:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐन. के. ऐफ. के. से ऐन. के. ई. बी. (184) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा -9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

ऐन. के. ऐफ. के. से ऐन. के. ई. वी. (184) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेंटीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तेलावी	236/37	0	01	68
	236/39	0	09	24
	236/40	0	05	76
	236/53	0	11	52
	236/34	0	16	80

[सं. O-12016/136/86-ओ. एन. जी.-डी.-4]

S.O. 3048.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKFK to NKEV (184) in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKFK to NKEV (184)

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Telavi	236/37	0	01	68
	236/39	0	09	24
	236/40	0	05	76
	236/53	0	11	52
	236/34	0	16	80

[No. O-12016/136/86-ONG-D-4]

का.आ. 3049.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.एन.सी.एच. से एस.एन.सी.एल. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस.एन.सी.एच. से एस.एन.सी.एल. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य:—गुजरात जिला व तालुका.—मेहसाना

गाव	सर्वे नं.	हेक्टयर	आरे.	सेन्टीयर
बलोल	1783	0	03	36
	1782	0	08	04

[सं. O-12016/137/86-ओ एन जी-डी 4]

S.O 3049.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCH to SNCL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that or the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura, Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNCH to SNCL

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Balol	1783	0	03	36
	1782	0	08	04

[No. O-12016/137/86-ONG-D-4]

का.आ. 3050 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी.जी.एस.-III से जी.जी.एस.-V तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी.जी एस. III से जी.जी.एस. V तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कलोल

गांव	ब्लाक न.	हैक्टेयर	आरे	सेन्टीयर
वडावस्वामी	267	0	19	50
	273	0	06	30
	272	0	14	70
	271	0	15	30
	कार्ट ट्रैक	0	01	05
	240	0	06	45
	239	0	06	90
	237	0	24	00
	233	0	21	00
	217	0	16	50
	234	0	01	60
	216	0	12	90

[सं. O-12016/138/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3050.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from GGS III to GGS V in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS III to GGS V

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Vadavswami	267	0	19	50
	273	0	06	30
	272	0	14	70
	271	0	15	30
	Cart track	0	01	05
	240	0	06	45
	239	0	06	90
	237	0	24	00
	233	0	21	00
	217	0	16	50
	234	0	01	60
	216	0	12	90

[No. O-12016/138/86-ONG. D-4]

का.आ. 3051:— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डबका जी.सी.एस. से सरसवणी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डबका जी.सी.एस. से सरसवणी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : पादरा

गांव	सर्वे नं.	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गवासद	627	0	10	24
	632	0	03	84
	633	0	03	76
	634	0	03	60
	635	0	06	48
	706/2	0	06	40
	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	650/3	0	03	20

1	2	3	4	5
	651	0	05	60
	652	0	02	40
	653	0	03	76
	655	0	01	60
	658/1	0	06	40
	665	0	10	40
	664/2	0	01	44
	669/1	0	03	68
	669/2/बी	0	10	40
	कार्ट ट्रैक	0	00	40
	671	0	03	60
	672	0	01	60
	670	0	01	60
	683	0	14	40
	689	0	11	36
	688	0	05	00
	687/2	0	01	76
	857	0	06	96
	कांस	0	02	72
	996/1	0	01	28
	996/2	0	01	60
	996/3	0	02	40
	996/4	0	02	40
	999/1	0	01	00
	1000	0	02	08
	1001	0	04	64
	कार्ट ट्रैक	0	00	64
	1033/1	0	02	40
	1033/2	0	00	96
	1032/2	0	02	32
	1032/3	0	00	80
	1031/3	0	01	28
	1031/2	0	02	24
	1029	0	00	64
	1030/1+2+3	0	04	80
	1026	0	04	80
	कार्टट्रैक	0	02	00
	7	0	00	48
	42	0	02	08
	43	0	04	00
	44	0	01	92
	45	0	11	04
	कार्ट ट्रैक	0	02	40
	46/1	0	01	60
	कार्ट ट्रैक	0	00	40
	106	0	04	88
	104/2	0	04	88
	104/1	0	04	10
	111/1	0	08	48

[सं O-12016/139/86-ओ एस-जी-डी]

S.O. 3051.—Whereas it appears to the Centra Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dabka G.C.S. to Sarsawani in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpur Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from G.C.S. to Sarsawani

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Padara

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	
Gavasad	627	0	10	24
	632	0	03	84
	633	0	03	76
	634	0	03	60
	635	0	06	48
	706/2	0	06	40
	Cart trac	0	01	20
	650/3	0	03	20
	651	0	05	60
	652	0	02	40
	653	0	03	76
	655	0	01	60
	658/1	0	06	40
	665	0	10	40
	664/2	0	01	44
	669/1	0	03	68
	669/2/B	0	10	40
	Cart track	0	00	40
	671	0	03	60
	672	0	01	60
	670	0	01	60
	683	0	14	40
	689	0	11	36
	688	0	05	00
	687/2	0	01	76
	857	0	06	96
	Kans	0	02	72
	996/1	0	01	28
	996/2	0	01	60
	996/3	0	02	40
	996/4	0	02	40
	999/1	0	01	00
	1000	0	02	08
	1001	0	04	64
	Cart track	0	00	64
	1033/1	0	02	40
	1033/2	0	00	96

1	2	3	4
1032/2	0	02	32
1032/3	0	00	80
1031/3	0	01	28
1031/2	0	02	24
1029	0	00	64
1030/1+2+3	0	04	80
1026	0	04	80
Cart tract	0	02	00
7	0	00	48
42	0	02	08
43	0	04	00
44	0	01	92
45	0	11	04
Cart tract	0	02	40
46/1	0	01	60
Cart tract	0	00	40
106	0	04	88
104/2	0	04	88
104/1	0	04	40
111/1	0	08	48

[No. O-12016/139/86-ONG-D-4]

का.आ. 3052.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2037 तारीख 7-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस बी ए ई से ऐस ओ बी सी टी एफ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर	सेन्टीयर
हेबुवा	276	0	16	56
	277	0	11	16
	279	0	09	36
	कार्ट ट्रैक	0	02	64
	54	0	02	16

[सं. O-12016/56/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3052.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2037 dated 7-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SBAE to SOB. CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectatre	Are	Centiare
Hebuva	276	0	16	56
	277	0	11	16
	279	0	09	36
	Cart tract.	0	02	64
	54	0	02	16

[No. O-12016/56/86-ONG-D4]

का.आ. 3052 यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2040 तारीख तारीख 12-5-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एस. बी. ऐ. डी. से एस. ओ. बी. जी. जी. एस.-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला व तालुका: मेहसाना

गांव	सर्वेन	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
जगुदन	464	0	06	60
	कार्टट्रेक	0	01	44
	639	0	09	12
	कार्टट्रेक	0	00	48
	640	0	05	04

[सं. ओ.-12016/59/86-ओ एन-जी-डी-4]

S.O. 3053.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2040 dated 12-5-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SBAD to SOB. GGS II

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Jagudan	464	0	06	60
	Cart tract	0	01	44
	639	0	09	12
	Cart tract	0	00	48
	640	0	05	04

[No. O-12016/59/86-ONG-D4]

का.आ. 3054.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1373 तारीख 16.3.86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. एम. डी. सी. से जी. जी. एस.-I

राज्य: गुजरात जिला: भरुच तालुका: झांगोट

गांव	ब्लाक सं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
रोहित	470	0	43	54

[सं. ओ.-12016/17/8 6-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3054.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 1373 dated 16-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therfore, in exercise of the power conefrred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of

this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SMDC to GGS I

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Rohit	470	0	43	54

[No. O-12016/17/86-ONG-D4]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1986

का. आ. 3055.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. जी. एस-III से जी.जी.एस-V तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जी.जी.एस-III से जी.जी. एक्स-V तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कलोल

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
छत्राल	282	0	21	00
	283	0	16	50
	कार्ट ट्रैक	0	01	50
	295	0	22	45
	294	0	00	75
	296	0	08	55
	298	0	05	85
	299	0	15	15
	302	0	07	80
	301	0	21	75
	332	0	10	80
	334	0	13	50
	337	0	15	30
	350	0	11	25
	349	0	12	75
	352	0	09	00
	354	0	10	65

[सं O-12016/140/86-ओएनजी-डी 4]

New Delhi, the 19th August, 1986

S.O. 3055.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum G.G.S. III to G.G.S. V in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GGS III TO GGS V.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Chhatral	282	0	21	00
	283	0	16	50
	Cart track	0	01	50
	295	0	22	45
	294	0	00	75
	296	0	08	55
	298	0	05	85
	299	0	15	15
	302	0	07	80
	301	0	21	75
	332	0	10	80
	334	0	13	50
	337	0	15	30
	350	0	11	25
	349	0	12	75
	352	0	09	00
	354	0	10	65

[No. O-12016/140/86-ONG-D 4]

का. आ. 3056.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी.जी.एस-III से जी.जी.एस-V तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी.जी.एस-III से जी. जी. एस VI तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कडी

गांव,	सर्वे नं०	हेक्टर	आरे,	सेंटीयर
चड़ासणा	4/1	0	07	85
	4/2	0	01	15
	3	0	15	00
	2	0	14	85
	1	0	27	00
	416	0	28	50
	416	0	31	50
	412	0	00	90

[सं. O-12016/141/86-ओ एन जी-डी-4]

पी. के. राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

S.O. 3056.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. III to G.G.S. VI in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practcitioner.

Pipeline from GGS III to GGS VI.
State : Gujarat District : Mehsana Tuluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chadasana	4/1	0	07	85
	4/2	0	01	15
	3	0	15	00
	2	0	14	85
	1	0	27	00
	416	0	28	50
	416	0	31	50
	412	0	00	90

[No. O-12016/141/86-ONG-D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

का.आ. 3057 :—कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 (1972 का 36) के खंड 20 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और श्री के.डी.शर्मा की भुगतान आयुक्त के पद पर नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना सं. 11024/3/84-सी ए दिनांक 25-10-1985 के अतिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) के अधीन नियुक्त भुगतान आयुक्त श्री ए आर मंडल को, कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 (1972 का 36) के द्वारा अथवा उसके अधीन भुगतान आयुक्त को सौंपे गए कामों के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 1986 से, अर्थात जिस तारीख को उन्होंने श्री के. डी. शर्मा से कार्य-ग्रहण किया उससे, भुगतान आयुक्त नियुक्त करती हैं ।

[फा.सं. 11024/1/86-सी.ए]

टी.सी. ए. श्रीनिवासन, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 14th August, 1986

S.O. 3057.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), and in supersession of the notification of Government of India, Ministry of Energy, Department of Coal No. 11024/3/84-CA dated 25th October, 1985 appointing Shri K. D. Sharma as Commissioner of Payments, the Central Government hereby appoints Shri A. R. Mandal Commissioner of payments appointed under the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973),

as Commissioner of Payments for the purpose of performing the functions assigned to such Commissioner of Payments by or under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972) with effect from the 30th April, 1986 (AN) on which date he took over the charge of office from Shri K. D. Sharma.

[F. No. 11024/1/86-CA]

T.C.A. SRINIVASAN, Director

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1986

का. आ. 3058.—केन्द्रीय सरकार, बहु राज्य, सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस. 11012/1/85-एल. एण्ड एम. दिनांक 28 जुलाई, 1986 का अधिक्रमण करते हुए कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में संयुक्त सचिव श्री के. राजेन्द्रन नायर को आगामी आदेशों तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है।

[सं. एल. 11012/1/85-एल. एण्ड एम.]

आर. एस. हंसरा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 18th August, 1986

S.O. 3058.—In exercise of the powers coferred by sub-section (1) of section 4 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) and in Supersession of the Notification of the Government of India No. L-11012/1/85-L&M dated the 28th July, 1986, the Central Government hereby appoints Shri K. Rajendran Nair, Joint Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) as the Central Registrar of Cooperative Societies until further orders.

[No. L-11012/1/85-L&M]

R. S. HANSRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1986

का. आ. 3059.—स्पेन, पुर्तगाल और बैलजियम से सूअर का गोस्त, सूअर का सुखाया मांस और सूअर के अन्य उत्पादों का इन देशों में अफ्रीकन सूअर के ज्वरग्रस्त होने की दृष्टि से भारत में आयात करने संबंधी लगे निषेध के बारे में इस विभाग की दिनांक 6 मार्च, 1986 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में भारत सरकार एतद्द्वारा नीदरलैंड्स से उपर्युक्त पशु धन उत्पादों का आयात करने पर निषेध लगाती है। क्योंकि अब अफ्रीकन सूअर के ज्वरग्रस्त होने संबंधी उक्त प्रकोप के उस देश में भी होने की सूचना मिली है। यह भी अधिसूचित किया जाता है कि वर्तमान निषेध, जोकि 6.9.86 को समाप्त होगा, उक्त तारीख से तीन महीने की अवधि के लिये और बढ़ाया गया है।

[सं. 50-43/85-एल.डी.टी. (ए. क्यू.)]

New Delhi, the 21st August, 1986

S.O. 3059.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated March 6, 1986, banning the import into India of swine, pork, ham and such other porcine products from Spain, Portugal and Belgium in view of prevalence of African Swine Fever in these countries, the Government of India hereby extends the ban to the import of the above livestock products from Netherlands, now that outbreaks of African Swine Fever have been reported from that country as well. It is further notified that the present ban which would expire on 6-9-1986 shall stand extended by a further period of three months from that date.

[No. 50-43/85-LDT (AQ)]

S. P. VERMA, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सर्वे एण्ड सैटलमेंट यूनिट-1)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1986

का.आ. 3060.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) की व्यवस्था के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखित भूमि आगे दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को आई.एन.ए. कालोनी, नई दिल्ली में इलैक्ट्रिक सब स्टेशन बनाने के लिए हस्तान्तरित करने के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय, निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दी है :—

अनुसूची

लगभग 375 वर्ग गज (लगभग 313.548 वर्ग मी.) माप का भूमि खण्ड जो आई एन ए कालोनी के पीछे स्थित है, जिसका प्लाट नं. रथल 47 है और जो अधिसूचना सं. एस ओ 1810 दिनांक 20-7-74 का आंशिक भाग है।

उपर्युक्त भूमि खण्ड की सीमाएं निम्नलिखित हैं :

उत्तर में : सड़क

दक्षिण में : सड़क

पूर्व में : राउन्ड अबाउट

पश्चिम में : महरोली रोड

[सं एस एण्ड एस 33(8)/84 एस ओ (1)/209]

एम. पी. जैन, सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Survey & Settlement Unit I)

New Delhi, the 5th August, 1986

S.O. 3060.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of Section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Government the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land and Development Office, Ministry of Works & Housing,

Government of India, New Delhi, for further transfer to Delhi Electric Supply Undertaking for construction of Elec tric Sub-station in INA Colony, New Delhi.

SCHEDULE

Piece of land mensuring about 375 Sq. Yds. (about 313.548 Sq. M.) situated behind INA Colony, New Delhi bearing site No. 47 partly of Notification No. S.O. 1810 dated 20-7-1974.

The above piece of land is Bounded as follows.—

North : Road

South : Road

East : Round about

West : Mehrauli Road

[No. S&S 33(8)/84-ASO(I)/209]
M. P. JAIN, Secy.
Delhi Development Authority

परिवहन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

का. आ. 3061.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (प्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार भूतपूर्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 684, तारीख 13 फरवरी, 1974 की, जहां तक उसका संबंध विमान पत्तन प्राधिकरण के सरकारी स्थानों से है, अधिक्रांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
प्रादेशिक नियंत्रक, हवाई अड्डा, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास और दिल्ली या उक्त अधिकारियों की अनुपस्थिति में उपनिदेशक (वायु मार्ग और हवाई अड्डा), मुख्यालय, राष्ट्रीय, विमानपत्तन प्राधिकरण	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित स्थान।

[सं. एवी. 21012/8/86-वीबी]
आर. एन. भार्गव, अवर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 14th August, 1986

S.O. 3061.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of notification of the Government of India in the late Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 684, dated the 13th of February, 1974, so far as it relates to the public premises belonging to the National Airports Authority, the Central Government hereby appoints the Officers of the National Airports Authority mentioned in column (1) of the Table below, being officers of equivalent rank of the Gazetted Officers of the Government, to be estate officers, for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in Column 2 of the said Table.

THE TABLE

Designation of Officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Regional Controller of Aerodromes, Calcutta, Bombay, Madras and Delhi or in the absence of any of the said officers, the Deputy Director (Air Routes and Aerodromes) at Headquarters of the National Airports Authority.	Premises under the administrative control of the National Airports Authority situated within the local limits of their respective jurisdiction.

[No. AV. 21012/8/86-VB]
R.N. BHARGAVA, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1986

का. आ. 3062.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने गिद्दड़बाहा टेलीफोन केन्द्र, उत्तर पश्चिमी सर्किल, में दिनांक 08.09.1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-23/86-पी एच बी]

के. पी. शर्मा सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

पी एफ संख्या 8-2/86-एसी

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 22nd August, 1986

S.O. 3062.—In pursuance of para (a) of Section II of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 08-09-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Gidderbada Telephone Exchanges N. W. Telecom Circle.

[No. 5-23/86-PHB]

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1986

का. आ. :—3063 आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने अहमदनगर टेलीफोन केन्द्र, महाराष्ट्र सर्किल में दिनांक 06-09-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-27/86 - पी एच बी]

के.पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

New Delhi, the 25th August, 1986

S.O. 3063.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 6-9-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Ahmednagar Telephone Exchanges, Maharashtra Circle.

[No. 5-27/86-PHB]

K. P. SHARMA, Assistant Director General(PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

शुद्धि पत्र

का.आ. :—3064 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में दिनांक 31 मई, 1986 को प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 30 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या का.आ. 313 (अ) में पृष्ठ 2 के कालम 2 के पैरा 3 में चौथी पंक्ति में "संबंध में मूल वेतन के" शब्दों के स्थान पर "संबंध में वर्तमान मूल वेतन के" शब्दों को पढ़ा जाए।

[वी 24032/6/86—डब्ल्यू बी)]

विशम्भर नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th August, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 3064.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 313 (E), dated the 30th May, 1986, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 31st May, 1986 at page 3, in column 1, for the words "per cent of basic wages" read "per cent of the existing basic wages".

[F. No. V-24032/6/86-WB.]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

का. आ. 3065 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, न्यू बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-9-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 20th August, 1986

S.O. 3065.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th August, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 46|86

In the matter of dispute between :

Shri J. K. Pangasa through The General Secretary Indian National Bank Employees Congress, 4058|36, Regl arpura, Karol Bagh, New Delhi.

VERSUS

The Chairman-cum-Managing Director,

New Bank of India, 1, Tolstoy Marg New Delhi.

APPEARANCES :

Workman in person.

Shri N. C. Sikri with Sh. Anil Singhal for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide notification No. J-12012(96)|85-D.IV(A) dated 3-4-1986 has referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of New Bank of India, Head Office, New Delhi in terminating the services of Shri J. K. Pangasa. Steno Typist with effect from 31-5-1985 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Notice of this reference has sent to the respondent Shri N. C. Sikri with Shri Anil Singhal appeared for the Management. The parties have filed a photostat copy of the order dated 22-7-86 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 8989-90 of 1985 J. K. Pangasa and another Vs. The New Bank of India and another which reads as under :

"The order of termination of service will stand withdrawn and the petitioners will be reinstated with full back wages. However, the Management will be at liberty to proceed in accordance with law.

The Writ Petitions are disposed of accordingly. No order as the costs.

New Delhi.

Dated July 22nd, 1986.

Sd|- illegible
(O. CHINNAPPA REDDY)
Sd/- Illegible J"

3. In view of the above order of the Hon'ble Supreme Court of India this reference has become redundant and is disposed of accordingly and No Dispute Award is given.

Further ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer
[No. L-12012|96|85-D.IV(A)]

July 29-7-1986.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1986

का. आ. 3066.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-8-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st August, 1986

S.O. 3066.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oriental Fire and General Insurance Company Limited and their workmen which was received by the Central Government on the 7th August, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA; PRESIDING OFFICER; CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL; NEW DELHI

I.D. No. 32|79

In the matter of dispute between :

Smt. Sushma Sharma, W/o Shri Sham Sharma, r|o 7|46A, Vijay Nagar, Delhi.

VERSUS

Oriental Fire and General Insurance Co. Ltd.

APPEARANCES :

Shri N. C. Sikri for the workman.

Shri C. J. Arora for the Managment.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide notification No. L-17012|16|78-D.IV(A) dated 12th June, 1979 has referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Oriental Fire and General Insurance Company Limited, New Delhi are justified in terminating the services of Shrimati Sushma Sharma, Assistant (Typing) with effect from the 18th September, 1975 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Some of the undisputed facts are that the workman was appointed as Assistant (Typing) with the respondent w.e.f. 17-3-75 vide letter dated 13-3-75. She was appointed on probation for a period of six months from the date of appointment which could be extended at the discretion of the Management. The performance of the workman during probation was not found to be satisfactory and her services were terminated on completion of probationary period vide letter dated 18-9-75. During her employment with the respondent the General Manager had made certain enquiries about the marital status of the workman and she had furnished her explanation.

3. The workman has challenged her termination on the grounds that the Management had become prejudiced because of the misunderstanding and confusion created by some vested interest about her marital status; that her performance during the probationary period was quite satisfactory; that her termination was discreminatory as some other probationers were given extension whereas she was not given any extension and that no reasons were given for her termination; and there was violation of principles of natural justice.

4. The Management denied the allegations of the workman and justified the order of termination. It was pleaded that the services of the workman were terminated on completion of probationary period as her performcane was not satisfactory and the order of termination is in the nature of termination-simplicitor and there is no stigma caused on the workman. The Management was within its right to terminate her services on the completion of the probationary period and it was under no obligation to give any reasons for the termination and there was no violation of the priniciples of nature justice which are not attracted in this case. It was further submited that enquiry regarding the marital status of the workman was made in a routine manner and, there was no nexus between the said enquiry and the termination order.

5. The workman has got a hopeless case. It was made clear in the letter of her appointment that she was on probation for a period of six months and the probationary period was liable to be extended. It was further made clear that her confirmation in service was not automatic. It was only on satisfactory completion of her probationary period or the extended probationary period that a letter will be issued confirming her services were terminated on 18-9-75 by a terming the probationary period were not found to be satisfactory and on completion of the progationary period her services were terminated on 18-9-75 by a termi nation order simplicitor. The Management was well within its right to terminate her services on completion of the probationary period. There was no obligation on the part of the Management to give any reason for the termination. The simple fact that her performance was found to be unsatisfactory during the probationary period does not cast any stigma on her and the provisions of Article 311 of the Constitution are not attrracted. Here claim that she was not given any chance for imporvement is deviod of any force because it was within the discretion of the Management whether or not to extend her probationary period. If the Management extended the probationary period of some other probationers, again it was well within its right to do so and no fault can be found with it. If any authorities are needed, reliance may be placed on the following two authorities :

1. AIR 1980 Supreme Court 1242 Oil and Natural Gas Commission and others Versus Dr. Md. S. Iskander Ali where it was held as under :

"Where the short history of the service of the probationer appointed in a temporary post clearly showed that his work had never been satisfactory and he was not found suitable for being retained in service and that was why even though some sort of an enquiry was started, it was not proceeded with and no punishment was inflicted on him and in these circumstances, if the appointing auothority considered it expedient to terminate the services of the probationer it would not be said that the order of termination attracted the provisions of Aricle 311, when the appointing authority had the right to terminate the service without assigning any reasons. In such a case even if misconduct, negligence, inefficiency might be the motive or the indusing factor which influenced the employer to terminate the

service of the employee a power which the employer undoubtedly possessed, even so as under the terms of appointment of the employee such a power flowed from the contract of service, termination of service could not be termed as penalty or punishment. Further adverse remarks in the assessment roll and recommendation thereinto extend the probationary period could not be said to indicate that the intention of the appointing authority was to proceed against the employee by way of punishment."

2. AIR 1981 Supreme Court 957 Union of India and others Versus P. S. Bhatt wherein it was held as under :

"The law in relation to termination of service of an employee on probation is well settled. If any order terminating the service of a probationer be an order of termination simplicitor without attaching any stigma to the employee and if the order is not an order by way of punishment, there will be no question of the provisions of Article 311 being attracted.

The respondent was appointed as an Announcer in the All India Radio. He was selected by direct appointment for the post of Producer and was appointed as such on probation. While he was on probation he was reverted to the post of Announcer. The respondent alleged that the motive behind the order was that he had indulged in loose talk and had used filthy language against his superior which was tape recorded and sent to the Station Director.

Held that the order was an order of termination of the employement on probation simpliciter and reversion to the old post without attaching any kind of stigma.

From the broad facts it is manifest that even if the conduct of respondent in indulging in loose talks and filthy and abusive language may be considered to be the motive or the inducing factor which influenced the authorities to pass the impugned order that order cannot be said to be by way of punishment. Decision of Andhra Pradsh Hihgh Court Reversed."

6. No doubt the Management had made some enquiries regarding the marital status of the workman and she had given her explanation in this regard but no nexus can be established between those enquiries and termination of the probationer. Although it was not necessary for the Management to do so, yet it has placed on record Ex. RX-2 in which a note was recorded by the Assistant Manager Personnel Department dated 5-5-75 to the effect that the performance of the workman was not up to the mark and she was found to be talkative which was not conducive to discipline in the department and the Manager Personnel Department asked Officer Incharge to speak to her and to report progress. and another not Ex.RX3 was recorded by the same Assistant Manager on 2-7-75 to the effect that there was no improvement in the work and general behaviour of the workman and he would prefer if she could be transferred to some other department and the Manager again ordered that progress should be watched and then the General Manager called for a Confidential Report from the Assistant General Manager Ex.RX1 which showed her conduct to be unsatisfactory and the General Manager ordered her termination. She has not alleged any malafides on the part of the Assistant Manager Personnel who had made the reports of unsatisfactory performance. She has alleged some vested interest at the back of the termination order but the vested interest has not been identified. The law is clear that the allegations of malafides have to be specific. Again during the evidence the allegation was made that one Mr. Mankat was hostile towards her because her father who had worked with the respondent was junior to him and they had differences and she was made a victim for this reason. However, this fact was not mentioned in the statement of claim or even in the rejoinder and hence must be ignored. Therefore, the allegations of malafides are not established.

7. It may be noted that the workman had completed only six months of service and she has not completed the statutory period of one year service with the respondent and hence she has not acquired any rights under the Industrial Disputes Act for reinstatement or compensation. As a last resort the Ld. representative of the workman stated that there is violation of section 30 of the Delhi Shops and Establishments Act which is reproduced below :—

"30. "Notice of dismissal"

(1) No employer shall dispense with the services of an employee who has been in his continuous employement for not less than three months, without giving such person at least one month's notice in writing or wages in lieu of such notice :

Provided that such notice shall not be necessary where services of such employee are dispensed with for misconduct, after giving him an opportunity to explain the charge or charges against him in writing.

(2) No employee who has put in three months continuous service shall terminate his employment unles he has given to his employer a notice of at least one month in writing. In case he fails to give one month's notice he will be released from his employment on payment of an amount equal to one month's pay.

(3) In any case instituted for a contravention of the provision of sub-section (1), if a Magistrate is satisfied that an employee has been dismissed without any reasonable cause or discharged without proper notice or pay in lieu of notice, the Magistrate may, for reasons to be recorded in writing, award, in addition to one month's salary compensation to the employee as follows :—

(a) Where immediately before his discharge or dismissal, the employee was in receipt of a salary not exceeding Rs. 1001- per month, such amount of compensation not exceeding his month's salary, as the Magistrate may direct,

(b) Where immediately before his dismissal or discharge, the employee was in receipt of a salary exceeding hundred rupees per mensem, such amount of compensation not exceeding hundered rupees as the Magistrate may direct.

(4) The amount payable as compensation under this section shall be in addition to any fine payable under section 40.

(5) No person who has been awarded compensation under this section shall be at libarty to bring a civil suit in respect of the same claim"

8. It is apparent that this section is self contained code and any violation of the same attracts penalty if a complaint is made before a Magistrate, and the workman is at liberty to make a complaint before the Magistrate but this section does not confer any rights under the Industrial Disputes Act.

9. In view of the discussion made above, it is held that the action of the Management of the Oriental Fire and General Insurance Company Ltd., New Delhi in terminating the services of Smt. Sushma Sharma w.e.f. 18-9-75 is justified and the workman is not entitled to any relief. This reference is disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer
[No. L-17012|16|78-D.IV(A)]

July 30, 1986.

नई दिल्ली, 26, अगस्त, 1986

का.आ. 3067.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मद्रास स्टीवडोर्स एसोसिएशन, मद्रास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, तमिलनाडु के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12 अगस्त, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 26th August, 1986

S.O. 3067.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Induustrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the mangaement of Madras Stevedores Association, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1986.

BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD, B.Sc., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL,

TAMILNADU MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Friday, the 1st day of August, 1986

Industrial Disputes No. 4 of 1984

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Indusutrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Maangement of Madras Stevedores Association, Madras-1)

BETWEEN

The workman represented by The General Secretary, Madras Port and Dock Workers Congress No. 7, Philips Street, Madras-600001.

AND

The Chairman, Madras Stevedores Association, 1st Floor, Madras Dock Labour Buildings, Rajaji Salai, Madras-600001.

REFERENCE :

Order No. L-33012/3/83-D.IV(A), dated 10-1-1984 of Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday the 22nd day of July, 1986 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru N.G.R. Prasad for Thiruvalargal Row and Reddy and R. Rajaram, Advocates appearing for the workman and of Thiru V. S. Neelakantan, Advocate for King and Patridge, Advocates appearing for the Management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

AWARD

This dispute between the workman and the Management of Madras Stevedores Association, Madras-1 arising out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-33012|3|83-D.IV(A), dated 10-1-1984 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue:

"Whether the action of the management of Madras Stevedores Association, Madras in dismissing Shri S. Veerappan, General Purpose Mazdoor Token No. 310, from service with effect from 9-6-1983, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

(2) It is submitted in the claim statement that the workman concerned in the dispute Thiru S. Veerappan was a Committee Member of the Madras Port and Dock Workers Congress and was employed as a General Purpose Mazdoor in the Respondent-Association. He had put in 14 years of service before his dismissal on 9-6-1983. It is stated that on 7-4-1983, the worker Thiru Veerappan went to the Call Point to receive his salary. He was asked by another co-worker Thiru Mian who belonged to rival Union to pay subscription to his Union. On his refusing to do so, Thiru Mian abused him in a filthy language and two other workers caught hold of him and tried to remove some money from his pocket. He was rescued with the help of others standing nearby and the Police were also present at the spot. Subsequently a charge memo dated 7-4-1983 was issued to the Petitioner alleging that he abused and assaulted Mian and removed Rs. 344 from his pocket and he was placed under suspension. It is stated that a detailed explanation denying the charges was submitted to the Respondent-Management on 18-4-1983. A domestic enquiry was conducted. Even though he had earlier taken part in the enquiry the latter part of the enquiry took place in his absence without notice having been sent to him. A copy of the enquiry proceedings was also not furnished to him and he was dismissed by any order dated 9-6-1983. The domestic enquiry held was illegal and was in contravention of principles of natural justice. The findings of the Enquiry Officer are perverse and not supported by evidence on record. According to the Petitioner, as he was an active member of the Union and insisting upon the Management to pay incentive arrears he had been victimised. Lastly, it is stated that the punishment of dismissal is out of all proportion to the gravity of the misconduct committed.

(3) In the counter statement filed on behalf of the Respondent-Management, the allegations made in the claim

statement are denied. It is stated that Thiru Veerappan was employed as General Purpose Mazdoor with effect from December, 1969. On 7-4-1983 he had abused and assaulted a co-employee Thiru Mian who belonged to a rival Union when he was collecting subscriptions from the workers without any provocation and under the influence of liquor. In the course of the incident he had also taken away a sum of Rs. 344 from Mian's pocket. Immediatey after the incident, on a report made by Thiru Mian, the Administrative Officer placed Thiru Veerappan under suspension by an order dated 7-4-1983 pending enquiry. In respect of the charge memo issued to him, the workman gave an explanation denying the charges. An enquiry was conducted, wherein the Petitioner had participated and cross-examined the Management witness. Even though the Petitioner was informed about the further enquiry being held on 11-5-1983 he did not choose to attend the enquiry at a later stage. A fair and proper enquiry was conducted in accordance with the Standing Orders and principles of natural justice. The findings of the Enquiry Officer were accepted by the punishing authority and the workman was dismissed from service on account of grave misconduct committed. The allegation of victimisation is denied. The order of dismissal is valid and justified for the misconduct committed by the Petitioner-workman.

(4) The point for adjudication as stated in the reference is :

> Whether the action of the management of Madras Stevedores Association, Madras in dismissing Shri S. Veerappan, General Purpose Mazdoor Token No. 310, from service with effect from 9-6-1983, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

(5) No oral evidence was adduced on either side Exs. W-1 to W-4 were marked on behalf of the Petitioner-workman and Exs. M-1 to M-13 relied upon by the Management.

(6) At the outset itself it may be mentioned that the workman concerned did not challenge the validity of the domestic enquiry on the ground of violation of the principles of natural justice or the Standing Orders. An endorsement was made by the learned counsel appearing for the Petitioner that the arguments are confined to the scope of Section 11-A of the Industrial Disputes Act. It is now well settled that under Section 11-A, the Tribunal can reappraise the entire evidence on record and come to an independent conclusion whether the allegations of misconduct levelled against the workman stand proved and also ascertain whether the punishment imposed is disproportionate to the grivity of the misconduct committed and grant appropriate relief depending upon the circumstances of the case.

(7) The workman concerned Thiru S. Veerappan was employed as a General Purpose Mazdoor in the Respondent-Association from December, 1969. On 7-4-1983, he was involved in an incident with another co-worker Thiru Mian. On a report being made by Thiru Mian about his having been abused and assaulted by Thiru S. Veerappan and deprived of a sum of Rs. 344, a charge memo Ex. M-2 dated 7-4-1983 was issued to the workman Veerappan and he was kept under suspension on the same day. The charge as detailed in Ex. M-2 reads as follows:

> Around 1500 hrs. on 7-4-1983 the said worker approached arrogantly Shri Miyan, G.P.F. No. 164, at the entrance of MSA Cal Point Office without being offended, caught hold of his collar, pulled him down and gave him blow below right collar bone. He used highly filthy language and challeged for kiling him at the top of his voice in prescence of all workers and Members of Staff who had assembled in connection with disbursement of lakhs of rupees. His said act created commotion to an extent that huge cash lying open at the counter was at stake. In the scuffle Shri Miyan's shirt was completely spoiled, buttons torn, and he lost Rs. 344/-. The situation could be controlled at the intervention of the Sub-Inspector.

The Petitioner submitted an explaination denying the charges levelled marked as Ex. M-3. As the Management had not satisfied with the explanation, an enquiry was conducted on the above charges. Ex. M-4 are the findings of the Enquiry Officer holding that the charges framed against the Petitioner-workman stood proved. Accepting the findings of the Enquiry Officer, the Petitioner was dismissed from service with effect from 9-6-1983 as disclosed by the order of dismissal marked as Ex. M-5.

(8) The learned counsel appearing for the Petitioner contended that on the evidence adduced in the enquiry, the charges framed against the Petitioner had not been established. In this context, it has to be noted that the charges relate to the Petitioner having abused Thiru Mian in filthy language and assaulted him and in the process deprived him of s. 344/-. As far as the charge of assault is concerned, the evidence of the witnesses examined in the enquiry clearly establishes that the workman Thiru S. Veerappan had assaulted him co-worker Thiru Mian in the presence of the other witnesses examined on behalf of the Management in the course of the enquiry. The defence set up by the Petitioner that Thiru Mian had abused him and that he was assaulted by two other workers supporting Mian's Union had been rightly rejected by the Enquiry Officer. However, it is pertinent to note that even though the Enquiry Officer had rightly not given any finding that the Petitioner-owrkman had taken away Rs. 344/- belonging to Thiru Mian he had concluded as follows : "These witnesses of the complainant gave out similar statements confirmed the assault of Miyan by the Respondent shouting in filthy language and under the influence of liquor." It is surprising to note that the Enquiry Officer should have added the words "under the influence of liquor" in his findings which is baseless and not supported by any evidence on record. As a matter of fact, even the charge issued to the Petitioner did not refer to any allegation that the Petitioner was under the influence of liquor at the time of the incident. The punishing authority in the order Ex. M-5 accepting the findings of the Enquiry Officer had stated as follows :

> "The Enquiry Officer has submitted his findings on 6-6-1983 holding that the charges levelled against you have been proved beyond reasonable doubt. We have perused the enquiry proceedings and the findings of the Enquiry Officer and other records and we concur with the findings of the Enquiry Officer and we find no material to agree with the explanation originally given by you in reply to the chargesheet. The charges proved against you are very serious in nature in that you behaved in a riotous and disorderly manner and indulged in serious act of violence during working hours creating commotion in the Call Point office. Therefore, however much we explore the possibility of finding out any extenuating circumstances in the matter of imposition of punishment, we find none. On the other hand the serious act of misconduct committed by you and proved against you warrants the imposition of the punishment of dimissal.
>
> Accordingly, you are dismissed from service with immediate effect. The period of suspension pending enquiry will be treated as leave on loss of pay and our Accounts Department is hereby directed to settle your accounts."

The punishing authority had rightly held the Petitioner guilty only for behaving in a riotous and disorderly manner and indulging in act of violence during working hours as the misconduct committed by him. It is no doubt true that the punishing authority had not specified under which category of the Standing Orders the misconduct committed is to be treated However, on a persual of Ex. W-4, the Standing Orders, if the allegations made in the charge are held to be proved, it would amount to misconduct under clause XV (3) of the Standing Orders, which reads as follows :

> "(a) The following shall constitute misconduct, generally meriting dismissal;
>
> (1).....
>
> (2).....
>
> (3) Unprovoked assault on a supervisory official or a co-worker at the place of work.

The workman had not raised any plea in the claim statement that the act of misconduct held proved against him does not amount to misconduct under the Standing Orders or that he had been deprived of any reasonable opportunity of putting forward his defence on account of full facts amounting to misconduct not conveyed to him.

(9) The only point that remains to be considered on merits is whether the misconduct committed would warrant the punishment of dismissal imposed on the workman. The incident in question admittedly was sparked of on the spur at the moment without any premeditation on account of inter-union rivalry. It is no doubt established that the workman had during working hours at the entrance of the Call Point Office abused another co-worker Thiru Mian and assaulted him by giving him a blow. The scuffle was stopped by the intervention of Sub-Inspector as disclosed by the charge memo Ex. M-2. In this context, it is relevant to to point out that Thiru Mian had given a complaint to the Police in respect of the incident, for which no action had been taken. As already adverted to the allegation that the Petitioner was drunk or that he had deprived Thiru Main of Rs. 344|- is baseless and not substantiated by the evidence on record. The punishing authority itself has not rightly given any finding on this aspect. The Petitioners act though not commendable in my view, would not justify the extreme punishment of dismissal from service. The workman concerned had put in nearly 14 years of service and had committed the act of assault in a state of indiscretion.

(10) The learned counsel appearing for the Respondent-Management contended that the past record of service of the workman was not unblemished and this had been taken into account by the punishing authority as stipulated by clause XVIII of the Standing Orders in awarding punishment of dismissal. On a persual of the exhibits on record it is evident that workman concerned had been given some minor punishments on some earlier occasions, but he had never indulged in any such act of assault or violence on a supervisory official or co-worker, during his entire tenure of service affecting the discipline of the Management-establishment.

(11) Taking the totallity of the circumstances, the punishment of dismissal imposed is held unjustified and grossly disproportionate to the gravity of the misconduct committed. In arriving at such a view, one has to taken into consideration the strata of society to which the workman belongs and the economic dependance of his family on his employment. Accordingly the order of dismissal is set aside and the Petitioner is directed to be reinstated in service without back wages, but with continuity of service on or before 1-10-1986 failing which the Petitioner would be entitled to full wages from 1-10-1986 till the date of reinstatement along with other attendant benefits. There will be no order as to costs.

Dated, this 1st day of August, 1986.

(Sd) Fyzee Mahmood
Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For workman : None.

DOCUMENTS MARKED

For workman

Ex. W-1|20-6-83—Letter from the Union to the Management regarding dismissel of Thiru S. Veerappan.

Ex. W-2|27-6-83—Letter from the Union to the Commissioner of Labour (Central), Madras for interference.

Ex. W-3|19-9-83—Standing orders for daily workers.

For Management

Ex. M-1|7-4-83—Complaint of Thiru K. Mian to the Police.

Ex. M-2|7-4-83—Charge memo to Thiru S. Veerappan.

Ex. M-3|18-4-83—Explanation of Thiru S. Veerappan.

Ex. M-4|18-4-83—Findings of the Enquiry Officer and Enquiry Proceedings.

Ex. M-5|9-6-83—Dismissal order issued to Thiru S. Veerappan.

Ex. M-6|11-11-76—Memo issued to Thiru S. Veerappan for his absence from duty.

Ex. M-7—Explanation of Thiru S. Veerappan to Ex. M-6.

Ex. M-8|19-9-78—Warning memo issued to Thiru S. Veerappan.

Ex. M-9|23-7-80— -do-

Ex. M-10|12-11-82— -do-

Ex. M-11|29-11-76—Report of the Assistant Sub-Inspector to the Commandant against Thiru S. Veerappan.

Ex. M-12|10-12-76—Suspension order issued to Thiru S. Veerappan.

Ex. M-13|14-2-77—Warning memo issued to Thiru S. Veerappan.

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal
[No. L-33012|3|83-D. IV(A)]
K. J. DYVAPRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

का. आ. 3068:—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 676, दिनांक 5 फरवरी, 1986 द्वारा इंडिया गवर्नमेंट मिन्ट, बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 फरवरी, 1986 से छः मास की कालावधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2के खंड (ङ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अगस्त, 1986 से छः मास की और कालावधि के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।.

[फा. सं. एस.-11017/3/85-डी.-1 (ए)]
शशि भूषण, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1986

S.O. 3068.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 676 dated the 5th February, 1986 the India Government Mint, Bombay to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 24th February, 1986;

And whereas the Central Government is of opinion that tpublic interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th August, 1986.

[No. S-11017|3|85-D. I(A)]
SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1986

का. आ. 3069.—मैसर्स वर्धमान टेक्सटाइल्स 2/3, इण्डस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना पी. एन./5861 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चंडीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014 (212)/86—एस. एस. —2]

New Delhi, the 20th August, 1986

S.O. 3069.—Whereas Messrs. Vardhman Textiles 213, Industrial Area-A, Ludhiana (PN/5861), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the estabilshment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this examption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee| legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(212)|86-SS(II)]

का.आ. 3070—मैसर्स यंग वूमैन्ज करीसचिन एसोसियेशन आफ देहली, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (डी.एल./1413) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है और जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(213)/86-एस.एस.-2]

S.O. 3070.—Whereas Messrs. Young Women's Christian Association of Delhi, Ashoka Road, New Delhi-110001 (DL/1413) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (c) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group nsurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable uunder this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this examption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee| legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(213)|86-SS-II]

का.आ. 3071.—मैसर्स एयो कमिकल्स एफ-214—215 रोड, 10, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर (आर.जे./3995) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उस की मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014(216)/86-एस.एस.-2]

S.O. 3071.—Whereas Messrs. Agro Chemicals, F-214-215 Road No. 10, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur (RJ/3995) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Jaipur, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Jaipur and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employers.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(216)|86-SS-II]

का. आ. 3072:—मैसर्स कर्नाटिका सिल्क इन्डस्ट्रीज लिमिटिड, यूनिट सिल्क फिलेचराज, टी. नरसीपुरा; 571124, मैसूर जिला (के. एन./957) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन, उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस.-35014(222)/86-एस. एस.-2]

S.O. 3072.—Whereas Messrs. Karnataka Silk Industries Corporation Limited, Unit Silk Filature, T. Narasipura-571124 Mysore Distt. (KN|957) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Grup Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee| legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(222)|86-SS-II]

का. आ. 3073.—मैसर्स कर्नाटका सिल्क इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटिड यूनिट मैसूर (के. एन./918) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2 क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3 क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब

उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014 (221)/86-एस. एस.-2]

S.O. 3073.—Whereas Messrs. Karnataka Silk Industries Corporation Limited Unit Mysore(KN|918) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-uection (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(221)|86-SS-II]

का. आ. 3074:—मैसर्स कर्नाटका सिल्क इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटिड, यूनिट स्पनसिल्क मिल्स, चेन्नापटना (के. एन. 47) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस.-35014 (220)/86-एस. एस.-2]

S.O. 3074.—Whereas Messrs Karnataka Silk Industries Corporation Limited, Unit Spunsilk Mills, Channapatna-571501 (KN|47) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, ithin 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(220)|86-SS-II]

का. आ. 3075.—मैसर्स कुमार साईकल इंडस्ट्रीज, 75-आर, इंडस्ट्रीयल एरिया बी, लुधियाना-141003 (पी. एन/2337) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप धारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय निर्दिष्ट करे,।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक की माह समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे,।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा,।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा,।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का यहां उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा,।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा,।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है,।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (217)/86-एस. एस-2]

S.O. 3075.—Whereas Messrs Kular Cycle Industries, 75-R, Industrial Area-B, Ludhiana-1410003 (PN|2337) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days fro mthe close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer

shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(217)|86-SS-II]

का. आ. 3079:—मैसर्स हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटिड, एस सी ओ. नं. 40-41, सैक्टर–17 ए, पोस्ट बैग नं. 22, चण्डीगढ़ (पी. एन/ 2830) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (12क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3–क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका

है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/215) 86 एस. एस-2]

S.O. 3076.—Whereas Messrs Haryana State Industrial Development Corporation Limited, S.C.O. No. 40-41, Sector 17-A, Chandigarh-160017 (PN|2830) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more avourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anyting contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No S-35014(215)|86-SS-II]

का. आ. 3077:—मैसर्स नरीमन पुआइंट विल्डिंग सर्विस एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि., एक्सप्रेस एस्टेट माउंट रोड, मद्रास 600002, (टी. एन. / 17824) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा 2 क के अधीन छूट किये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा यदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी लाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के किर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014 (214) /86-एस. एस -2]

S.O. 3077.—Whereas Messrs Nariman Point Building Services & Trading Pvt. Limited, Express Estates, Mount Road, Madras-600002 (TN|17824) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and maintain such accounts and provide such facilities for

inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a memoer of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madras and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(214)|86-SS-II]

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1986

का. आ. 3078.—मैसर्स कर्नाटका सिल्क फिलेचराज कार्पोरेशन लिमिटेड यूनिट, सिल्क फिलेचर, कनकपुरा जिला बंगलौर (के. एन./917) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकाशन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमे संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सभी सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014(223)/86-एस. एस.-2)]

New Delhi, the 21st August, 1986

S.O. 3078.—Whereas Messrs. Karnataka Silk Industries Corporation Limited Unit, Silk Failure, Kanakapura, Distt. Bangalore (KN|917) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satified that employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourabe to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All epenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment evempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Not withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014 (223)/86-SS-II]

का. आ. 3079.—मैसर्स कर्नाटका मिल्क इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि., रजिस्टर्ड ऑफिस 3 और 4 मंजिल, पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग, एम. जी. रोड, बंगलौर (के. एन. 9777) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो, यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014(224)/86-एस. एस.-2]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 3079.—Whereas Messrs. Karnataka Silk Industries Corporation Limited. Office III & IV Floor, Public Utility Building, M.G. Road, Bangalore-1 (KN|97773 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees, Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter refered to as the said Scheme) ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The empoyer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shal be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Empolyees' Provident Fund or the Providen Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain coverd under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(224)|86-SS-II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1986

का.आ. 3980..औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मैसर्स सिंगरैणी कॉलरीज कम्पनी लिमिटेड, मण्डामारी और रामाकृष्णापुर डिवीजन, डा० कल्याणीखानी जिला अदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-8-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd August, 1986

S.O. 3080.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur Division, P.O. Kalyani Khani, Distt. Adilabad (A.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th August, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 15 of 1985

BETWEEN

The Workmen of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur Division, Adilabad District A. P.

AND

The Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur Division, Adilabad, A.P.

APPEARANCES :

Sarivasri A. K. Jayaprakash Rao and P. Damodar Reddy, Advocate—for the Workmen.

Sarvasri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Kumari G. Sudha, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/67/64-D. III(B) dated 16th March 1985 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1) (d) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur Division and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Messrs Sigareni Collieries Company Limited, Mandamarri & Ramakrishnapur Division, P.O. Kalyani Khani District, Adilabad (AP) are justified in refusing confirmation as Chargehand Grade 'C' and also payment of officiating allowance with effect from 1-1-1979 to Shri Nimbaiah, Cat-IV Turner, Mandamarri Workshop? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 15 of 1985 and notices were issued to the parties.

2. The claims statement filed by the workmen of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Rama-Krishnapur Division stating that the Management is not justified in refusing confirmation as charge hand Grade C and also payment of officiating allowance with effect from 1-1-1979 to Sri T. Nimbaiah Category VI Turner working in Mandamarri Workshop. It is the case of the worker that the dispute of Nimbaiah was espoused by the Singareni Collieries Engineering Workers Union, MMS Ramakrishnapur and that Nimaiah worked in Category VI. He is the member of the Petitioner-Union. It is their case that he was appointed as Turner on 3-7-1961 in Category IV and Nimbaiah passed 10th Class and happens to be holder of I.T.I. certificate. It is also mentioned that he was officiating Charge hand Grade C in regular vacancy at Mandamarri Workshop since 1-1-1979 and the Management having extracted the work as charge hand C Grade, failed to pay any officiating allowance and Nombaiah is a qualified Turner with I.T.I. certificate having passed H.S.C. examination. It is also mentioned that he was called for interview while filling up the vacancy and it is also mentioned that the said vacancy was not filled till now and Sri Nimbaiah is officiating as Grade C charge hand in regular vacancy. It is also pointed out that Charge hand Grade C is a promotional post and all the workmen who have completed five years of service in Category VI eligible for promotion as Grade C charge hand. But the Management called other employee excluding Nimbaiah for interview. All those who have completed five years of service from Category VI were called for interview giving a go-bye to their own rules and practice. That those persons who called for interview expressed that they are not interested in the promotion still Nimbaiah is not given the requisite confirmation as charge hand C grade while officiating in the said post for many years and it amounted to victimisation and unfair labour practice. It is also mentioned that the Management agreed to observe uniform policy and guidelines to all the three Collieries with regard to calling for interview of VI category for interview Chargehand C Grade and failed to observe the same though Nimbaiah is officiating as Grade C charge hand in a regular vacancy for more than three years and such he is eligible for confirmation to Grade C chargehand. The action on the Management in refusing confirmaion to him as chargehand Grade C is arbitrary, unjust and illegal.

3. The Management on the other hand filed a counter denying all the allegations from para 3 onwards of the petition. It is mentioned that Nimbaiah was appointed as Turner on 3-1-1961 and subsequently promoted to Category V and VI and he is at present working in Category VI and it was a fact that he was holding I.T.I. Certificate. But it is incorrect to allege that Nimbaiah was officiating as chargehand Grade C. The allegation that he acted as officiating chargehand Grade C since 1-1-1979 is not correct. He was never authorised a chargehand and moreover a clear vacancy of chargehand mechanical section at K.K. Workshop Mandamarri. So the question of acting as charge hand Grade C did not arise. As per the seniority list Nimbaiah stands 10th man and as such he was not called for test out of the nine persons, out of those who have passed the trade test. According to them vacancies were filled according to merit. It is the case of the Management that Nimbaiah was not eligible to sit for the trade test. He was not called for examination that he was not eligible to sit for the trade test. Further it is mentioned that when vacancies arose for charge hand post in Mechanical Section of K.K. Workshop in 1983, 9 candidates at the rate of 1:3 was called for trade test and interview in the order of seniority and three vacancies were filled up on the basis of merit. So it is not correct to say that there were two vacancies of C Grade chargehand and these vacancies were not filled up till today. Moreover one Balalingam is working as charge hand C grade in regular vacancy, K.K. Workshop and thus there is no vacancy for Nimbaiah to officiate.

(a) Basically as per the Company's rules those who have completed five years of service are eligible for qualified trade test and only on passing the trade test they will be promoted as charge hands. But it is not correct to allege that whoever completes five years of service in Category VI will be given promotion automatically to C Grade as charge hand No employees has right to claim promotion to higher category by mere qualification and service. He must not only pass Trade test but also must have seniority/merit as per availability of vacancies to get promotions. So far as Sri Nimbaiah is concerned he being the tenth man in the seniority list he can only be called for future vacancies for the test and interview. Therefore the Management did not do any injustice to him.

(b) The workmen misconstrued the instructions in the circulars issued by the Management though two candidates called for interview remained absent for interview without prior intimation to the Management. Nobody brought to the notice of the Management. Even Sri Nimbaiah did not bring it to the notice of the Management about their absence prior to the completion of the test. The Management is not aware that those persons did not attend the test due to paralysis. The Management in all good faith as per the records called on the basis of 1:3 ratio candidates and out of nine candidates they are selected eligible candidates for the post of chargehand on seniority basis. It is again reiterated that the promotion is not automatic and it is incorrect to allege that Nimbaiah was eligible for automatic promotion. The Management followed the uniform policy in all the areas and there is no disproportion and thus the question of victimisation and unfair labour practice did not arise. The Management agreed before the Conciliation authority that all the three Divisions i.e. Bellampally, Mandamarri and Ramakrishnapur are treated one area for purpose of promotion so far as the vacancies and promotions are concerned Nimbaiah if he officiate in higher category or grade must have been paid officiating allowance but he cannot be promoted to the post of charge hand just because he was directed to undergo training in Metrology and in Engineering Inspection. The promotion to higher category depends upon several factors like seniority/suitability/availability of vacancies etc. So the Management states that there is no point in seeking for confirmation to the post of charge hand as claimed.

4. The workman examined himself as W.W1 and marked Exs. W1 to W16. The Management examined M.W1 and marked Ex. M1 to M15.

5. W.W.1 mentioned that he passed H.S.C. and underwent as Turner in I.T.I. and he was trained in Metrology in Engineering Inspection and that he is a Member of the S.C. Engineering Workers Union which is a registered Union. According to him from 1-1-1979 he was officiating as C Grade chargehand. The turner post is in category VI. The next promotion is charge hand C grade post provided he is S.C.C. passed and also I.T.I. Turner and he also had requisite qualification and experience and seniority. It is his case that Rajanarsu who is junior to him as Turner was given officiating allowance as charge hand C Grade from 1981, 1982 and 1983 and Rajanarsu was promoted as Turner in 1966 and he had no educational qualification or technical qualification and thus Rajanarsu who is General Mazdoor given promotion as Turner.

(a) It is his case that at Mandamarri Workshop there are two charge hand vacancies and only one post is filled in 1983. In the other post of chargehand C Grade he was officiating since 1979. According to him at Bellampally where he worked the Management adopted a peculiar procedure by saying that there should be forevery charge hand 'C' post, three Turners should be called for interview at the rate of 1:3 and saying that 6 turners are not available for the 2 posts they are not calling him for interview to regularise his services as chargehand 'C' though he has put in 7 years service. Infact it is his case that superior like Executive Engineer, Chief Engineer, General Manager recommended his case to the Executive Director for regularising his services as Chargehand 'C' Grade and also recommended for payment of officiating allowance and that he gave a representation also to the Management. He marked the representation of his as Ex. M1 and the recommendation of the Executive Engineears Ex. M2. The representation made by him to the General Manager, Mandamarri and Ramakrishnapur Divisions marked as Ex. M3 and the same was also recommended by the Additional Chief Mechanical Engineer under Ex. M4. He also marked another recommendation letter dated 2-1-1983 by the Deputy Chief Engineer, Mandamarri to the Additional Chief Engineer, Bellampally under Ex. M5. According to him his name at S. No. 1 in Ex. M5. It is his case thereafterwards the General Manager, Mandamarri and Ramakrishnapur Divisions wrote a letter dt. 6|8th March 1983 to the Executive Director, Bellampally with regard to selection of two charge hands for Machine Shop Mandamarri and Ramakrishna pur and his name stood at S. No. 1 and 7 is the same is Ex. M6. The letter of the Deputy Chief Engineer, Mandamarri dated 12-6-1983 to the Additional Chief Engineer, Bellampalli is marked as Ex. M7. According to him in Ex. M7 it is mentioned that Nimbaiah and K.I Sataiah is senior to Dosari Posham and S. Rajanarsu and he filed Ex. M8 particulars of Category VI trademen that he stood at S. No. 1 and that he is suitable for promotion. The report submitted by the Superintendent, Industrial Engineering, Mandamarri. The Deputy Chief, Industrial Engineering, Bellampalli is marked as Ex. M9. He filed Ex. M10 as the copy of the promotion as charge hand Grade C. According to him when there are two posts of charge hands the other person who was promoted as charge hand Grade C at S. No. 2 K. Swamy did not join duty. he asserted as per Ex. M10 it would show that there were two vacancies and they tried to fill up the two posts also and K. swamy did not turn up even after calling for interview and yet he was officiating in the said vacancy. It is his specific case that he should have been selected as charge hand Grade C in that vacancy and that he mentioned as per Ex. M11. The Management was adopting victimisation process by stating that they are calling for 1:3 while in other trades like Metrology they called candidates eligible at the rate of 1:2. He filed Ex. M12 photostat copy of the circular issued by the Management with regard to charge hand Grade C. According to him he had minimum qualification of I.T.I. and S.S.C. as required for charge hand Grade C. To show that he worked as charge hand Grade C. He showed to the management challan written in his own hand which issued indent which is otherwise know as challan book marked Ex. M13. It is his case that he showed that he was officiating as charge hands Grade C. He also mentioned that he maintained shift report book for Turners and machinist and the same is counter signed by Divisional Engineer under Ex. M14. The Union representation is marked as Ex. W1 and his representation given to the Executive Director is marked as Ex. W2. The Instructions given by his superiors showing that he should work as charge hand Grade C are marked as Exs. W3 to W10. So he wanted that he should be confirmed as charge hand Grade C from 1-1-1979.

6. M.W1 mentioned that he is the Divisional Engineer working in Kalyani Khani Workshop since 1983 and that chargehand Grade C is a person who will supervise the work of Turners and they discharge the duties properly and also maintains several records. He denied that Nimbaiah ever officiated as charge hand Grade C. According to him Nimbaiah is only a Turner on Lathe machine and he is paid wages Category VI as a Turner. The General Manager authorise the person to be a chargehand Grade C when there is a post and when it is clear vacancy. According to him one Balalingam is working as charge hand Mechanical section, K.K. Workshop and he is promoted as charge hand Grade C in 1983 and they wanted one more chargehand and wrote to the General Manager to supervise the work of Turner in back shifts. According to him Nimbaiah the 10th man at the time of interview was conducted for charge hand Grade 'C and therefore he was not eligible for the test and he was not called for the examination and in 1983 for the three vacancies of charge hand in Mechanical Section of K.K. Workshop and other Division of Bellampalli and Ramakrishnapur 9 candidates were called for the test and interview in the ration of 1:3 and he mentioned that he was not aware whether there are any vacancies in Bellampalli,, Mandamarri and Ramakrishnapur He could not say whether that there were two vacancies of chargehand and thus are not filled till today. He denied the suggestion that who ever completed five years of service in Category IV will be given permission automatically to Charge hand Grade C. Witness added it is not existing at the time of his deposition. According to him he came in 1983 to this Workshop and from the records it is found that he is not authorised to work as charge hand Grade C from 1979 to 1983. So when he is not authorised the question of giving officiating allowance did not arise.

7. The admitted facts of the case are that Sri Nimbaiah was appointed on 3-7-1961 as Turner Category IV and subsequently promoted to Category V and VI and finally he is working in Category VI. It is also admitted that he is holding I.T.I. and that he passed 10th Class. The same is not denied in the counter or in the evidence of the Management. Therefore, it is taken for granted that he passed 10th Class also. The reference is to the effect whether the management of Singareni Collieries are justified in refusing confirmation as charge hand grade 'C' and also payment of officiating allowance with effect from 1-1-1979 to Nimbaiah Category IV. It might be at the time when the dispute was raised Nimbaiah was in Category IV and now on the date of filing the counter by the Management he was working in Category VI. Sri G. Sudha counsel for the Management contended the Nimbaiah is styled as Category IV Turner and the matter is referred whether justified in refusing confirmation of the charge hand in Grade 'C' and therefore it is not about confirmation as charge hand. She tried to distinguish the reference by stating that this reference did not relate to non-confirmation as charge hand Grade 'C' and that it is only about refusal. A careful reading of the reference would not show that there is any such distinction to be drawn. The refusal is with reference is whether the Management is justified in refusing confirmation as charge hand Grade 'C'. It cannot be said that this Tribunal if it holds that refusal of confirmation as charge hand Grade 'C' on merits, that it is nothing short of not conforming charge hand Grad C and it is beyond its scope is perhaps untenable and not accentable. Of course it must be seen from the reference whether the facts placed before the Tribunal would show that the Management is not justified in refusing confirmation.

8. It is no doubt true that charge hand Grade 'C' is a promotion and for promotion as charge hand Grade C there are certain guidelines and as mentioned in Ex. M15. According to the Company's rules the person who completes 5 years of service he is eligible to sit for trade test, only after passing the trade test he will be promoted as charge hand and it is mentioned by the Management that Seniority/merits as per availability of vacancies will also be taken into con-

sideration and that Nimbaiah was not eligible to sit for the trade test as he stood 10th man in the seniority list and therefore he was notcalled for trade test when the three vacancies were identified in Mechanical Section and 9 candidates at the rate of 1 : 3 were called for in the order of seniority and those three vacancies were filled up on the basis of merits It is the Managements case thus that there is no vacancy for Nimbaiah. The Petitioner workman on the other hand mentioned that he is officiating Charge hand Grade C in regular vacancy at Mandamarri Workshop from 1-1-1979 till the date of filing the claims statements and that he had all the requisite qualifications and he was not called for interview by the Management by adopting unfair labour practice as a sort of victimisation against him by not calling him for interview.

9. First of all taking for granted it is a selection post and it requires seniority-cum-merit and availability of vacancies and technical qualifications and that promoting one person from one category to other is not auotmatic and therefore confirmation will not arise even if it accepted as a proper principle the question is whether the Management applied the said principle in the case of Nimbaiah correctly, properly and strictly adhering to the rules as well as the guidelines mentioned in Ex. M15 or not. The arguments of the Management is that since Nimbaiah was never appointed temporary as charge hand Grade C the question of confirming him as charge hand Grade C did not arise and the reference itself is outside the purview since no confirmation could be there when there is no appointment. Well this is point which workers is fighting stating that he is officiating as chargehand Grade C from 1-1-1979 and the Management is extracting work from him as chargehand Grade C without giving him appointment order. So the appointment order which is a paper order is not the criterion. The point to be seen is strictly, what is the nature of work taken from he concerned workman and the said workman duty involved the duty of the category of charge hand Grade C or in the lower category of Turner so as to say that he is officiating or not officiating or that he is appointed or not appointed or that he is eligible or not eligible. So the crux of the problem is what is the nature of work that is extracted from Nimbaiah since 1-1-1979 ? If it is the Managements case that they did not extract any work as charge hand Grade C then the Management is within its right to say that such work as chargehand Grade 'C' being a promotion by seniority-cum-merit etc., and being not automatic he should not seek for such confirmation when there is no such discharge of duties of the classified category.

10. So thus this matter has to be analysed in this context. The evidence of W.W. 1 would show certain facts. He passed H.S.C. and also underwent I.T.I. Turner in Metrology and Engineering Inspections, and he is a member of the Union, Singareni Collieries Engineering Workers Union. The Turners post is in Category VI. According to him the next promotion for which he is entitled is chargehand Grade C, and he had the requisite qualifications and experience. He mentioned that Rajanarsu who is a General Mazdoor who is given Turner post though he had no educational qualification in 1966 while both of them joined service in 1961 while himself as Turner and Rajanarsu as mazdoor. It is also asserted by him that in Mandamarri Workshop there are two charge hands Grade C posts vacant and one post is filled in 1983. As charge hand Grade C one is expected to supervise the work of Turners and their machines and as charge hand Grade C one allocates the work and report their working and submit report. It is the case of W.W. 1 Nimbaiah that he was allocating and also making reports of the work of Turners and also submitting reports and also issuing transport and finishing goods prepared by the Turner and that his case was always recommended for payment of officiating allowance. Now Ex. M1 is the application of Nimbaiah recommended by the Executive Engineer under Ex. M2 dated 30-6-1980 it indicated tha the Executive Engineer mentioned that they were not having charge hand or machine shop on their rolls and to have effective supervision in back shifts atleast they require two charge hands for Machine Shop and that Nimbaiah is regular in his duties and he knows various jobs that are normally carried out in Mandamarri Workshop and that his application should be considered for chargehand post in Machine Shop after test. Ex. M3 showed that the applications of T. N Nimbaiah was forwarded showing that T. Nimbaiah is working as Category VI Turner at Kalyani Khani Workshop with qualification and experience and from the Circular dated 22nd May, 1976 para 5 that Nimbaiah is eligible for charge hand Grade C for Mechanical Workshop. The Additional C.M.E. quoted all the relevant rules in the said circular dated 22nd June, 1976 and stated that Nimbaiah is eligible as charge hand mechanical. He further mentioned that in para 3 of Ex. M3 when there is requirement of charge hands in K.K. Workshop as there are lathes, one milling machine and one Welding machine and one Rail Driller and other machines working in Mandamarri Workshop in all the three shift. It is further mentioned that the said circumstances T. Nimbiah could be subjected to a test and promoted as charge hand Mechanical machine Workshop, Mandamarri if he found fit. So all these guidelines which are stated in Ex. M15 which charge hand should have namely that he should have been I.T.I. Turner passed H.S.C. and he should have sufficient experience as Turner were all possessed by T. Nimbaiah. How it cannot be said that on the face of Ex. M3 dated 18th December, 1982 that there is no requirement of charge hand as suggested to W.W.1 and now tried to be set up through M.W.1. In fact the evidence of M.W.1 would show that one Balalingu working as charge hand in Mechanical workshop K.K. was promoted as charge hand in 1983 and they wanted one more charge hand and routed his application through the General Manager because they require for supervision of the Back shifts of Turners. The averment of M.W.1 that there is no charge hand post in Industrial Engineering Department made a study in the year 1981 falls to the ground. He himself admitted that there was a interview for K.K. Workshop charge hand Grade C conducted in 1982 and the Management adopted 1 : 3 ratio 9 persons as per their seniority from Turner to Grade C charge hand and on the ground that Nimbaiah happened to be 10th man in seniority he was not called for interview. First of all he came in 1983 as Divisional Engineer and he did not work from 1979 to 1982 at Kalyani Khani Workshop. M.W.1 admitted that Additional C.M.E. is superior Officer to him and he also conceded that Balalingu who is the charge hand Grade C did not pass H.S.C. examination and that K. Swamy and Balalingu charge hands C. did not pass H.S.C. and he could not say that there are rules to show that people should be called at the ratio of 1 : 3 as per the vacancies for the post of charge hand Grade C. According to him there is an agreement to that effect he conceded that under Ex. W13 he forwarded the joint application of Adam and H. S. Hussain to Additional C.M.E. question was put to M.W.1 whether these two applicants expressed their inability for going to the Trade test Infact the letter is sent through Divisional Engineer to Additional C.M.E. to the Executive Director and it clearly mentioned that both H. S. Hussain and D Adam mentioned that they were hardly having one year service and now they were at the fak end of their service and they were not prepared to withstand the trade test and they wanted them to be considered for charge hand C Grade without conducting the trade test and they should be assessed only on available assessment reports. In fact Ex. W14 would show that Dy. C. E. Bellampally area was bringing to the notice of the General Manager and Additional C.E. and Divisional Engineer that the total strength of Turners, Machinists and Punchmen at K.K. Workshop is 30 and as per the norms they require three charge hands whereas there is one charge hand on the rolls at K.K. Workshop. He requested that two more charge hands be filled in at K.K. Workshop where Nimbaiah is evidently working. Now Ex. W15 incidentally would show that Additional C.M.E. is mentioned to the Deputy Chief Engineer that as per the Tradesmen agreement 1975 dated 22-5-1976 that they require a charge hand to the Machine workshop in Mandamarri and another charge hand at Auto Workshop and as they were finding very difficulty for arranging supervision for these two since they were 25 Turners in Machine Section due to the dire necessity the Exective Engineer Workshop has utilised the service of T. Nimbaiah Category VI Turner who has got good qulifications and knowledge in the job. It is also mentioned therein that T. Nimbaiah has acted through proper channel on 21st June 1980 for elevating as charge hand 'C' and the Department so far did not take any action to initiate on his request. It is further mentioned that a person is being given after allowance for working in RKP Workshop that T.Nimbaiah also requested for similar facility and finally the Additional C.M.E. said that they requested the higher authorities to fill up the charge hand at Machine workshop. Ex. W15 is a clear indication that T.Nimbaiah whose services "were utilised as charge hand Grade C" and he had got good qualification and know-

lodge in the job and his case was recommended for the said post as he satisfied tradesmen agreement 1975 and that there was also a vacancy and demanded for filling up the vacancy in the Machine workshop Mandamarri as well as Auto Workshop Mandamarri, infact Ex. W16 would show that G.Latchman, Welder Tradesmen Machine Workshop who is the technical Grade C was designated as charge hand personal to work in Main Workshop, Kothagudem with immediate effect as per order dt. 25-2-1982 and that the said post is personal to him this will not be treated as vacancy and that it will be adjusted against the vacancies that may arise in future. This would itself would show that no trade was conducted, and the Welder tradesmen was promoted as charge hand 'C' if the Management so desired. Thus it is not a case where Nimbaiah did not apply through proper channel for his application being routed for trade test. It is not the case of the that he is not qualified or experience or did not satisfy the trademen agreement of 1975.

M. W1 admitted that apart from Ex. W15 that Nimbaiah is qualified and he is I.T.I. certificate holder in Turner and he is having experience as required. Now the very Ex. W13 as well as Ex. W16 would that some of the employees who were working as Category IV were promoted as Charge hand C Grade without holding any trade test and subsequently they were absorbed permanently in C Grade and in fact the Executive Director himself signed Ex. W16 dated 25th February, 1985 whereunder G. Latchman who is Welder was absorbed as charge hand C Grade and his signature is identified by M.W.1. Now having conceded as Nimbaiah has officiated as charge hand C Grade by M.W.1 and as is also admitted in Ex. W15 it is too much to say that Nimbaiah is not entitled for officiating allowance or that he did not at all officiate as charge hand Grade C. So so the necessary date which is available with the Management is not filed by the Management to controvert the documentary evidence of the workman as now available. There is no rule in the Standing Orders that for every vacancy only three persons who are eligible should be sent for trade test. Further when K. Swamy of Bellampally and Balalingam of K.K. Workshop when not having requisite qualification were permitted as charge hand C Grade and as admitted by M.W1 Ex. W16 as well as M.W1 would show that Latchman, Welder was also promoted as Charge hand C Grade without any trade test. Ex. M2, M3, M4, M5, M6 and M7 would show that all the Officers who are well acquainted with the nature of the work were recommending the case of Nimbaiah for promotion on the basis of all the available rules and provisions as he satisfied all the requirements and that he was also officiating in the said post. Ex. M10 clearly showed that K. Swamy as well as Balalingam were posted at K.K. Workshop as charge hand C grade and they did not pass the requisite qualifications. Ex. M14 would show that Bellampally Deputy C.E. wanted three charge hands and that he had only one person and on the basis of Ex W15 and all these documents it is needless to say that there is need for the charge hands C Grade at K.K. Workshop and that there was dire necessity for charge hand Grade 'C' and they were taking the services of Nimbaiah as the charge hand since the said vacancy is not filled. Ex. M12 is the agreement clause 5 prescribes the qualification for charge hand mechanical and it is evident as per the recommendations of all these people that Nimbaiah satisfied all the requirements and his application was also forwarded and recommended also. On the mere score that he was 10th man his application was withheld without conducting trade test though the evidence would show that Adam and H. S. Hussain wanted that they should not be conducted trade test for them as they were at the fag end of their retirement and not prepared and that the evidence of W.W1 would show that as per Ex. M10 K. Swamy and Balalingam did not possess requisite qualifications and further to substantiate his case that he worked as charge hand C Grade. W.W1 asserted that he wrote the Management challan books in his own handwriting with duplicate copies of revenue indent book requests and issue indent which is otherwise known as challan book more under Ex. M13. So Ex. M13 is clear documentary evidence and truth to say that he officiated as charge-hand Grade C the work report book known as Shift Report book A Turner is maintained by charge hand C Grade and counter signed by the Divisional Engineer. The same is marked as Ex. M14. Therefore Exs. M13 and M14 would satisfy the requirement to show that the said T. Nimbaiah was performing the duties of charge hand Grade C and that he was also officiating as charge hand C Grade.

Further to show that he was working as Charge hand C Grade and that he was issuing slips and that he was given instructions to do the work as charge hand C Grade by issuing slips to him by his superiors. He marked Ex. W3 to W10 which are issued by the Divisional Engineer, Deputy C.M., Assistant Engineer as the case may be. So when these documents Exs. W3 to MW10 coupled with Ex. M13 and M14 clearly satisfied and further when there is admission from the management on their part that his services were utilised as mentioned in Ex W15. It is futile to contend that his services were never utilised as charge hand C Grade. The rejection of his application for trade test when he had requisite qualification with experience seems to be a motivated and unfair labour practice in the guise of practice or convention said to be adopted inviting the candidates in the ratio of 1 : 3 which is not found anywhere in the rules. In fact this ratio is also given a go bye when K. Swamy and Balalingam were selected as charge hand C grade under Ex. M10 without trade test. Latchman was absorbed from the Welders post to charge hand under Ex. W16 when they are not having requisite qualifications and when they have not been conducted the trade test. W.W1 asserted that he was officiating charge hand since 1st January, 1979 and one and a half years thereafterwards he applied for regular service for charge hand for which Ex. M2 to M4 were the recommendations made by the Departmental authorities. In fact he clearly mentioned that the Assistant Engineer Ramachander and others under he worked will speak of his work that he would there as charge hand ever since 1979 if they are summoned and yet the Management did not dare to summon any of the Engineers. He quoted the name of B. Ramachander, Junior Engineer in the Machine Workshop and stated that he took work from him as charge hand C Grade from 1st January, 1979. The Management dare not examined B. Ramachander and there is no whisper that B. Ramachander was never there in the said Machine Workshop at the relevant time.

Further even if by way of argument if it is having such a convention to interview at the rate of 1 : 3 and nine candidates who were senior to him were really called for interview for the trade test, the Management is aware that six of them who were seniors did not attend the trade test Atleast the evidence would show that Adam and H. S. Hussain did not go for the trade test. Ex. W11 and W13 would show that some of them did not sit for trade test and infact it is denied that W11 & W13 were prepared subsequent to the trade test is over. So when there are vacancies and T. Nimbaiah is eligible and some of the people who were called for interview by the Management did not come for the interview, it is futile to say that even that socalled convention of calling the eligible candidates at the rate of 1 : 3 ratio was strictly adhered in the case of Nimbaiah. The truth seems to be a kind of purposeful and want on mischief and the same is nothing short of unfair labour practice and therefore the Management especiall when the entire people who were supervising his career recommended from this that he was officiating as charge hand 'C' and the records Ex. W3 to W10, M13 and M14 show that he officiated and that the Engineers were extracting work as charge hand from 1-1-1979. On a careful consideration I hold that Nimbaiah supervised the duties of other Turners as indicated under Ex. M14 and that he was issuing challan and maintaining book under Ex. M13 and thus with all experience and qualifications and eligibility even without the trade test is entitled for promotion with others were exempted giving the same benefit. The Management purposefully and knowing fully well that 1:3 ratio was not properly adhered to and even when it is adhered to that when some candidates refused to participate in the trade test by not allowing Nimbaiah to sit for the trade test when it is recommended by his superiors on three occasions committed unfair labour practice to follow their own convention if any and thus his promotion though it was not automatic on the basis of the requisite qulifications was strictly based upon the seniority cum merit and also on availability of vacancies and technical qualifications He had seniority cum merit and availability of vacancy is established beyond reasonable doubt and it is nobodys contention that he had no technical qualifications. Thus looked from any angle it seems to me that the Management of Singareni Collieries Company Limited are not justified in refusing confirmation as charge hand C Grade to T. Nimbaiah with effect from 1-1-1979 with all the benefits including officiating allowance and other attendant benefits. He is entitled for the relief : charge hand C Grade from 1-1-1979.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 22nd day of July, 1986.

J. VENUGOPALA, RAO, Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Workmen :		Witnesses Examined for the Management :	
W.W.1	T. Nimbaiah	M.W.1	M. A. Ansari

Documents marked for the Workmen :

Ex. W1 Representation dt. 30-11-84 made by J. Durgaiah, President, Singareni Collieries Engineering Workers' Union to the Executive Director, Singareni Collieries Company Limited, P.O. Bellampalli, Adilabad District with regard to confirmation of T. Nimbaiah as a 'C' Grade charge hand in regular vacancy.

Ex. W2 Representation dt. 1-7-82 made by T. Nimbaiah to the Executive Director, Bellampalli Collieries with regard to promotion to 'C' Grade charge hand to him.

Ex. W3 Instruction Slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by the Assistant Engineer.

Ex. W4 Instruction Slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by Junior Engineer, M.M. Workshop.

Ex. W5 Instruction Slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by the Divisional Engineer.

Ex. W6 Instruction Slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by the Management.

Ex. W7 Instruction Slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by the Divisional Engineer.

Ex. W8 Instruction Slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by the Junior Engineer.

Ex. W9 Instruction Slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by the Management.

Ex. W10 Instruction slip to work as charge hand 'C' issued to T. Nimbaiah by the Executive Engineer.

Ex. W11 Representation dt. 20-6-83 made by S. M. Hussain and D. Adam respectively to the Executive Director, S.C. Co. Ltd., Bellampalli Area with regard to promote them as charge hands without conducting test.

Ex. W12 True copy of the Representation dt. 14-6-80 made by T. Nimbaiah to the Divisional Superintendent, Mandamarri Division, with regard to promotion to highly skilled Tradesmen.

Ex. W13 Photostat copy of the Representation dt. 20-6-83 made by S. M. Hussain and D. Adam respectively to the Executive Director, S.C. Co. Ltd., Bellampalli Area with regard to promote them as charge hands without conducting test.

Ex. W14 True Copy of the Letter No. ACE/BPA/44/1427, dt. 9-10-85 addressed by Dy. CE, BPA (Area) to P.M., BPA with regard to charge hands for Machine Shop of KK Workshop.

Ex. W15 Photostat copy of the letter No. Dy. CE/MM/82/4/104, dt. 22-6-82 addressed by Addl. CME, MM to the E.D.BPA with regard to posting of charge hand in the Machine Shop in Mandamarri Division Workshop.

Ex. W16 Photostat copy of the Office Order dt. 25-2-1985 issued to G. Laxmaiah by the Executive Director, S.C. Co. Ltd., Kothagudem.

Documents marked for the Management :

Ex. M1 True copy of the Representation dt. 14-6-80 made by T. Nimbaiah to the Divisional Superintendent, Mandamarri Division, with regard to promotion to highly skilled Tradesman to him.

Ex. M2 True copy of the letter No. EE(W)/MM/80/21/358, dt. 30-6-80 addressed to Dy. CE, MM & RKP by Y. Rama Mohan Rao, EE(W) MM with regard to forwarding the application submitted by T. Nimbaiah.

Ex. M3 True copy of the letter dt. 18-12-82 addressed to GM MM & RKP by S. K. Garg, Additional CME, MM with regard to the application of T. Nimbaiah.

Ex. M4 True copy of the letter No. Dy. CE/MM/82/4/104, dt. 22-6-82 addressed to ED/BPA by the Additional CME/MM with regard to posting of charge hand in the Machine Shop in Mandamarri Division Workshop.

Ex. M5 True Copy of the elter No. Dy. CE/MM/83/4/4/10, dt. 2-1-83 addressed to Additional CE/BPA by V. Ramakrishna Dy. CE/MM/RKP with regard to posting charge hands at MM & RKP work shops and RKP Garage.

Ex. M6 Letter 6/8-3-83 addressed by GM, MM RKP to EDBPA with regard to selection of two charge hands for Machine Shops at MM and RKP workshop.

Ex. M7 Letter No. DYCE/83/4/622/4, dt. 12-6-83 addressed to Additional CE, BPA by the Dy. CE, MM & RKP with regard to particulars of Cat. VI Tradesmen of MM/RKP Workshops.

Ex. M8 Statement showing the particulars of Cat. VI Tradesmen.

Ex. M9 True Copy of the Letter No. MIF.78/81/58 dt. 30-1-81 addressed to Dy. Chief IE BPA by SIE, MM & RKP with regard to requirement of charge hands in MM & RKP Areas.

Ex. M10 True copy of the Office Order No. P. BPA/180/3117 dt. 9/10-10-83 issued to D. Balalingam and 3 others by the Executive Director, S.C. Co. Ltd., Belliampalli.

Ex. M11 True copy of the letter No. PBPA/180/1576, dt. 3/5-6-83 addressed to P. S. Bhasker, by Dy. CPM/BPA with regard to Selection of Tradesmen from amongst Cat. VI & Charge Hands to higher categories as Supervisors.

Ex. M12 Photostat copy of the Circular No. P4/2940/1143 dt. 10-6-1970 with regard to appointments & promotions.

Ex. M13 Revenue Indent Book.

Ex. M14 First Shift Report Book of Turners and Machinists from 6-6-1983 to 19-9-1983.

Ex. M15 Photostat copy of the letter No. P. 49/3369/2280, dt. 22-5-1976 addressed to Addl. G.M. Kgm. Addl GM, BPA, Addl.. GM, R.G. I and Addl. GM. RG II by the General Manager SC Co. Ltd., with regard to Discussions with the union about tradesmen.

Dated : 24-7-86.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-22012/67/84-D-III(B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1986

का. आ. 3081—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-8-86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 28th August, 1986

S.O. 3081.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to management of Vehicle Factory, Jabalpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th August, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(70)/1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of Vehicle Factory, Jabalpur and their workman, Sri Ghasiram Bhumaya, Labour 'A' Grade of Vehicle Factory, Jabalpur, C/o. Shri Sharda Prasad Tiwari (Teach Vill., Jodhpur) Post Office Tilwaraghat, Jabalpur (M.P.)

APPEARANCES :

For Workman—Shri M. L. Jain, Advocate.

For Management—Shri A. K. Chaube, Advocate.

INDUSTRY : Vehicle Factory DISTRICT : Jabalpur (M.P.)

AWARD

Dated : August 1, 1986

This is a reference against the removal of workman, Shri Ghasiram Bhumaya, Labour 'A' Grade from service with effect from 26-11-1982 made by the Central Government vide Notification No. L-14012(8)/84 D.II(B) dated 12th August, 1985, for adjudication. The terms of reference are as under :—

"Whether the action of the management of Vehicle Factory, Jabalpur (M.P.) in awarding punishment of removal from service Sri Ghasiram Bhumaya Labour 'A' Grade with effect from 26-11-1982 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case of the management is that on the intervening night of 6-7th October, 1981 workman along with others was found gambling with cards in the factory premises of the Vehicle Factory, Jabalpur. Therefore after the necessary departmental enquiry he was removed from service, it being his second offence.

3. The workman has challenged the enquiry before me. I framed the following issues which with my reasons and findings are as under :

ISSUES

1. Whether the enquiry is proper and legal ?
2. If not, whether the termination of the workman is justified on facts of the case ?
3. Whether the punishment awarded is proper and legal ?
4. Relief and costs ?

FINDINGS :

4. Issue No. 1.—I have gone through the enquiry papers and I find that Shri Ramdeo Ram and Shri C. S. Mishra both C.M. and F.M. Security were examined on 8-6-1982. Shri S. C. Bhattacharya, Foreman, Security was also examined on the same day. The first two witnesses were first examined by the Presenting Officer and then cross-examined by the workman, Shri Ghasiram. Thereafter the Enquiry Officer cross-examined witnesses at length brinnging out certain material facts which were not brought out in their examination-in-chief. Similarly Shri S. C. Bhattacharya, Foreman, was first examined by the Presenting Officer and then cross-examined by Shri Ghasiram and thereafter he was allowed to be re-examined by the Presenting Officer bringing out certain material facts which were not brought out in the examination-in-chief. This is not only highly prejudicial to the defence of the workman but also shows the prejudice of the Enquiry Officer. I, therefore, hold that the Enquiry was neither legal nor proper and it is vitiated.

5. Issue No. 2.—I have gone through the evidence of these witnesses and I find that none of these prosecution witnesses state specifically that the workman was seen gambling by them. They are not even able to say whether he had seen any cards in his hand or money in his pocket. In fact, cards and petty amount of Rs. 1.40 P. were found lying on the spot. This evidence is not enough to conclude that he was found gambling. In anny case certain incriminating evidence that he was found sitting with the gamblers when he was found gambling. In any case certain incriminating cross-examination of the Enquiry Officer and the re-examination by the Presenting Officer which part of the evidence to my mind ought to be ignored as being contrary to natural justice. I thus find that it is not proved that he was found gambling and therefore his removal is not justified. I hold and decide this issue accordingly.

6. Issue No. 3.—On perusal of record I find that on 5-5-1982 the charges were read to the workman and the case was fixed for evidence. The severe punishment of removal has been meted out to him perhaps on his previous conduct which alleged to be his second offence. But the records nowhere show the evidence regarding his previous conduct. In any case the previous bad record or the previous offence was not put to the workman either at the stage of charge or when he was examined. Therefore the same could not have been taken into consideration, I, therefore, find that the punishment meted out to him is also excessive and not proper. I hold and decide this issue accordingly.

7. Issue No. 4.—The management has nowhere asked for an opportunity to prove the misconduct before this Tribunal in their written statement or rejoinder. Therefore in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Firestone Tyre & Rubber Co. of India (P) Ltd. Vs. Management of Firestone Tyres Rubber Co. of India (P) Ltd. (1973-1-LLJ p. 278 SC) I have heard the parties finally on merits and therefore hold that since the domestic enquiry is vitiated the workman, Shri Ghasiram Bhumaya, Labour Grade A is entitled to be reinstated. Further looking to the circumstances of the case I do not consider him fit to allow him back wages. Reference is, therefore, answered as under :—

That the action of the management of Vehicle Factory Jabalpur (M.P.) in awarding punishment of removal from service to Sri Ghasiram Bhumaya, Labour 'A' Gr. with effect from 26-11-1982 is not justified. Therefore he is entitled to be reinstated but without back wages. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer
[No. L-14012/8/84-D.II(B)]

Dated : 1-8-1986.

का. आ. 3082—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, आर. एम. एस., जबलपुर विभाग के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-8-86 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3082.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Gov

dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of R.M.S. Jabalpur Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th August, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Case No. CGIT/LC(R)(26)/1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of R.M.S. Jabalpur Division, Jabalpur (M.P.) and their workman Shri F. K. Monkar, Sorting Asstt. represented through the P&T Employees Coordination Committee, Jabalpur (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Management—None.

INDUSTRY : P & T. DISTRICT : Jabalpur (M.P.).

AWARD

Dated, 1-8-1986

This is a reference made by the Central Government for adjudication of the following dispute vide Notification No. L-40012//85-D. II(B) dated 10-2-1986 :

"Whether the action of the management of RMS Jabalpur (M.P.) in terminating the services of Sri F. K. Monkar, Sorting Assistant vide order No. K-5-9/J8/83-84 dated 4-8-84 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The case of the workman is that he was appointed as Sorting Assistant on 23-12-1982 and he was doing his work satisfactorily and efficiently. However, because of the political rivalry Shri Madan Pandey, Acting Secretary of R.M.S. Union was annoyed with the petitioner. He exerted pressure on the Superintendent of R.M.S. Jabalpur through Shri N.J. Ayar, General Secretary, All India R.M.S. Union and Shri Samar Mukerjee, Member of Parliament and General Secretary of C.I.T.U. to take action aganist the workman. Shri Monkar belong to Schedule Caste. Therefore Shri Panday has even implicated him in a criminal case.

3. In the Annual Report of All India R.M.S. Union Class II from 1-5-1982 to 30-6-1982 they have admitted that the Union have complained to the Directorate, Hon'ble Minister and Post Master General to take action against him. Because of this pressure the workman was first transferred to Satna by order dated 26-5-1984 and then ultimately his services were terminated vide order dated 4-8-1984. Inspite of notice the management refused to participate before the Assistant Labour Commissioner (Central) Jabalpur.

4. The termination of the workman amounts to retrenchment within the meaning of Sec. 25F provision of which have no been complied with. Therefore the termination is void ab initio. There is no reason or justification for the termination in view of his excellent record of his service.

5. On receipt of the reference management was noticed number of time but they neither appeared nor perhaps being the postal authorities returned the postal receipts. Ultimately they have to be served personally but they failed to appear and did not put up any defence or any prayer to prove the misconduct, if any, before this Tribunal.

6. Workman has filed his own Affidavit and relied on documents Ex. M|1 to Ex. W|6. Ex. W|1 is his appointment order dated 23-12-1982 which mentions that his appointment is purely temporary and his services could be terminated by giving one month's notice etc.

7. It is now well settled as has been laid down in the case of State Bank of India Vs. N.S. Money (AIR 1976 SC 1111) that termination for whatsoever reason amounts to retrenchment. Therefore Section 25F of the I.D. Act will come into play. It requires one month's notice indicating the reason for retrenchment. In the instant case the dismissal order Ex. W|4 dated 4-8-1984 does not state any reason for his dismissal. Thus it contravenes the mandatory provision of Sec. 25F of the I.D. Act (Vithalbhai B. Patel's book "Law or Industrial Disputes Vol. I Third Edn. page 833 relied on). Therefore his services though temporary could not have been terminated without assigning any reason.

8. Next it has been contended that since the management neither gave one month's notice nor paid one month's salary in lieu of notice as envisaged under Sec. 25F of the I.D. Act the order of dismissal is void ab initio. Admittedly no notice was given but the order Ex. W|4 mentions that he shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice. To my mind this amounts to making an offer of the pay in lieu of notice and it is sufficient compliance for the purpose of I.D. Act as has been laid down in the book "Law on Industrial Disputes by Vithalbhai B. Patel Vol. 3rd Edn. page 773.

9. Next document relied on the Annual Report of R.M.S. Union from 1st May 1982 to 30th June 1984 (Ex. W|2) the material portion of which are reproduced below :

Similar is the case of Jabalpur Station. S|Shri Kesrilal "Sonkar and F.K. Mankar Stg. Assts. created terrorism. There also administration upto Circle level was giving protection to them. When the matter was brought to the notice of the Hon'ble Minister, after making enquiries by an officer of Directorate, ordered the P.M.G. to take severe disciplinary action against them and advised the P.M.G. to consider the cases of their transfer. In both cases all this ill elements have become the members of B.R.M.S. Union which are giving full support of their action."

10. The case of the workman is that on such pressure he was transferred to Katani vide order dated 26-5-1984 (Ex. W|3) and his services were terminated vide Ex. W|4 dated 4-8-1984. No redress was given to him inspite of his petition Ex. W|5 to the Hon'ble Minister for communication. Looking to Ex. W|2 there appears to be substance behind the contention of the workman in his unchallenged Affidavit. The management has not appeared to refute these allegations. I, therefore, find them proved. Thus it amounts to victimisation and unfair labour practice. Besides it is also in contravention of the provisions of Sec. 25F of the I.D. Act.

11. I therefore answer the reference as under :

That the action of the management of RMS Jabalpur Division, Jabalpur (MP) in terminating the services of Shri F.K. Monkar, Sorting Assistant vide order No. K-5-9|J8|83-84 dated 4-8-1984 is not justified. He is entitled to be reinstated with full wages, continuity of service and all ancillary benefits with effect from 4-8-1984. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No. L-40012|7|85-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1986

का. आ. 3083.—भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 1-3-86 को प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 921, तारीख 20 फरवरी, 1986 का अधिक्रमण करते हुए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 (ii) में 6 अगस्त, 1984 को प्रकाशित, भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या 567 (अ) दिनांक 21 मई, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

इस अधिसूचना में क्रमांक (5) में उल्लिखित नाम के स्थान पर निम्नलिखित नाम रखा जाएगा :—

"(5) श्री एन. के. खुराना — नियोजक के प्रतिनिधि
संयुक्त निदेशक,
मैकेनीकल इंजीनियरिंग (ईंधन)
परिवहन मंत्रालय, रेल विभाग,
(रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली।

[सं. एस-32019/4/83-डब्ल्यू. सी. (एम डब्ल्यू)]
ए. के. लूथरा, उपसचिव

New Delhi, the 28th August, 1986

S.O. 3083.—In supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 921 dated the 20th Feb., 1986 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 1st March, 1986 and in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (i) of the Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the Ceneral Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Deptt. of Labour) No. S.O. 507(E) dated the 21st May, 1984 published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3 (ii) dated the 6th August, 1984; namely :—

In the said notification the name mentioned at serial number (5) shall be substituted as under :—

"(5) Sh. N. K. Khurana, Employer's representative.
Joint Director,
Mechanical Engineering (Fuel).
Ministry of Transport,
Deptt. of Railways,
(Railway Board),
New Delhi."

[No. S-32019/4/83-W.C.(M.W.)]
A. K. LUTHRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986